



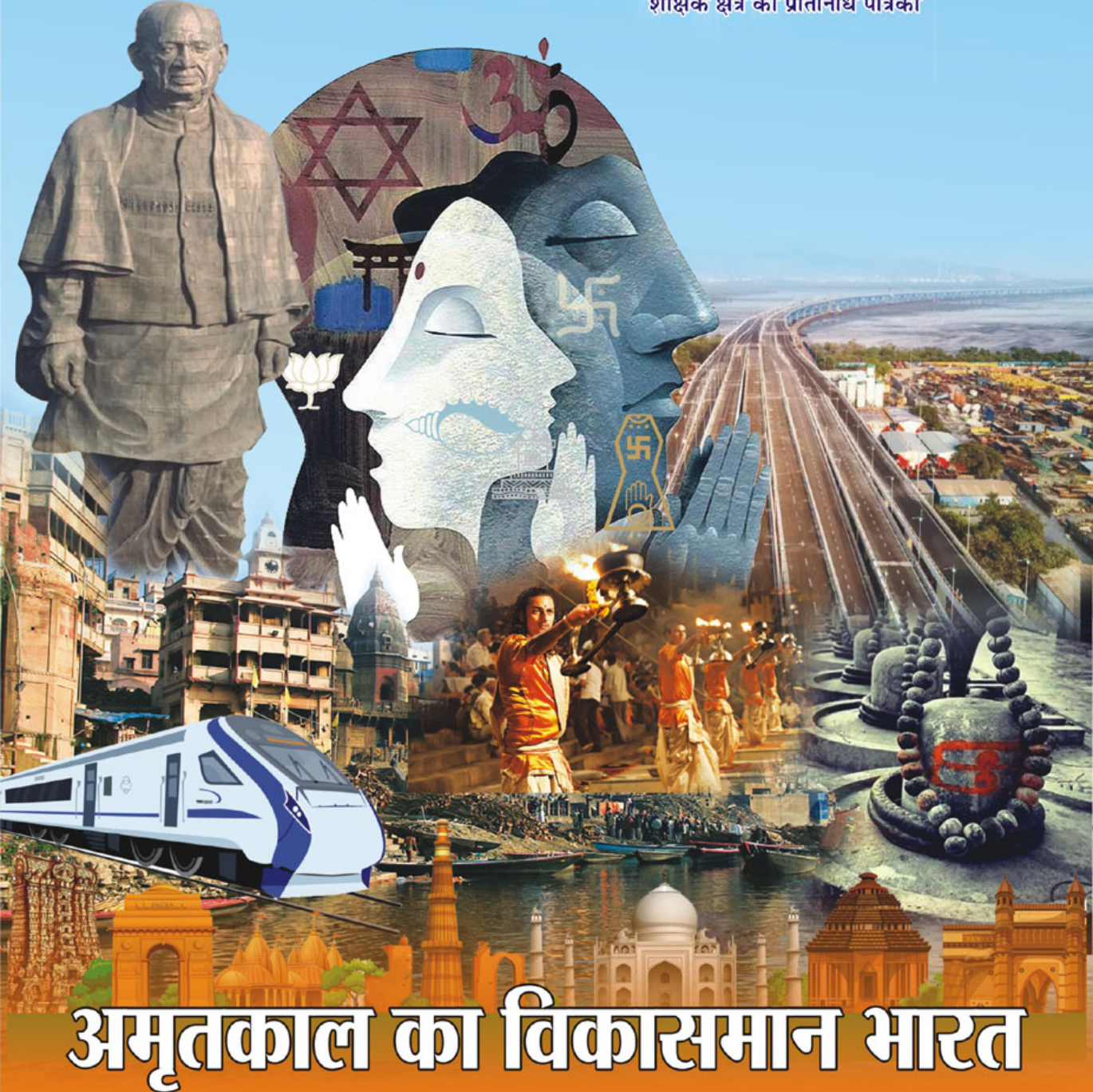
वर्ष : 16 • अंक : 10 • पृष्ठ : 44 • जयपुर  
www.shaikshikmanthan.com

ISSN 2581- 4133

वैशाख, विक्रम संवत् 2081  
1 मई 2024 • ₹ 25/-

# शैक्षिक मंथन

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका



## अमृतकाल का विकासमान भारत

# शैक्षिक मंथन

(द्विभाषी मासिक)

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 16 अंक : 10 1 मई 2024

बैशाख, विक्रम संवत् 2081

परामर्श

डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल

जगदीश प्रसाद सिंघल

शिवाणन्द सिन्दनकेरा

जी. लक्ष्मण

महेन्द्र कुमार



सम्पादक

प्रो. शिवशरण कौशिक



संपादक मंडल

प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय

प्रो. राजेश कुमार जागिड़

प्रो. ओमप्रकाश पारीक

डॉ. एस.पी. सिंह

प्रो. दीनदयाल गुप्ता

भरत शर्मा



प्रबन्ध सम्पादक

महेन्द्र कपूर



व्यवस्थापक

बसंत जिंदल



प्रेषण प्रभारी : नौरंग सहाय 'भारतीय'

प्रकाशकीय कार्यालय

82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,

जयपुर (राजस्थान) 302001

दूरभाष : 9414040403

दिल्ली ब्यूरो :

शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13,

कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली - 110053

E-mail :

shaikshikmanthan@gmail.com

Visit us at :

www.shaikshikmanthan.com

वार्षिक शुल्क ₹ 250/-

दस वर्षीय शुल्क ₹ 2000/-

पृष्ठ संयोजन : सागर कम्प्यूटर, जयपुर

शैक्षिक मंथन मासिक में प्रकाशित सामग्री से संपादक मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा चित्रों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है।

देश में अमृत काल में निर्धनता उन्मूलन के अप्रतिम प्रयास □ प्रो. राजेश कुमार जागिड़

तेज गति से आर्थिक विकास देश में सभी के लिए आय सृजन के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ सरकार के जन कल्याण पर अधिक प्रयास की क्षमता को बढ़ाता है। पिछले एक दशक में भारत आर्थिक विकास के कारण 'सबसे कमजोर पाँच अर्थव्यवस्था' समूह से निकलकर 'सबसे बड़ी पाँच अर्थव्यवस्थाओं' के समूह में सम्मिलित हो गया है। निर्धनता निवारण के अध्ययन यह इंगित करते हैं कि अमृतकाल



में भारत में अति निर्धनता लगभग समाप्त हो गई है। साथ ही पिछले 9 वर्षों में ( इसमें कोविड-19 संकट की अवधि भी सम्मिलित है) भारत में 24.92 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं।

## अनुक्रम

3. संपादकीय - प्रो. शिवशरण कौशिक
8. विकेंद्रीकरण : अमृतकाल में भारत में रोजगार वृद्धि... - प्रो. सुशील कुमार बिस्नू
11. अमृतकाल के विकासमान भारत में कौशल विकास... - प्रो. राजेश कुमार जोशी
14. अमृतकाल की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उन्नत भारत - डॉ. अंजनी कुमार झा
16. अमृतकाल और शिक्षा - डॉ. सतेंद्र कुमार शुक्ल
19. अमृतकाल : भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी - प्रो. मनीषा शर्मा
21. अमृत काल के भारत में पं. दीनदयाल उपाध्याय... - डॉ. धीरज कुमार पारीक
24. अमृतकाल का भारत और आधारभूत विकास - डॉ. अरविन्द पारीक
26. Bharath and its Brief History on Peace... - Dr. G.V.Snidgha Raj
30. Rising Bharat and NEP 2020 - Chandan K. Panda
33. Vikasit Bharat & Sustainable..... - Dr. R. K. Chaitanya
37. Bharat's Amrit Kaal : The Vision of ... - Darshan Kumar
39. Amrit Kaal's Hydroponic Harvest ... - Dr. Gurdev Chand
42. Holistic Learning : AmritKaal's ... - Ajay Maini

**Vikasit Bharat Is Not a Dream but It Will Be Reality By 2047**

□ Dr. Karrnati Kiran Kumar

**Next 25 years India needs to be under the strong leadership and government as we have right now. Under the visionary leadership only country can become Vikasit Bharat by 2047. If we look into the world, All the developed and even some of the developing countries either have two-party or single party system. They have clear cut agenda that is national interest. Country like India we have multiparty system across the country. Each party has its own agenda rather than national interests.**



28





प्रो. शिवशरण कौशिक  
संपादक

मनुष्य और पशु में सबसे बड़ा अंतर ऊर्ध्वोन्मुख चेतना का है जो उसे प्रकृति के अनेकानेक रहस्य जानने और उनको परिस्थितिजन्य इच्छित स्वरूप देने में समर्थ बनाती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जीवन-दर्शन में प्रकृति पर विजय प्राप्त करने या प्रकृति के विध्वंस से कोई अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं रही। मनुष्य का आत्म-चैतन्य उसमें सदैव नवीन ऊर्जा और नई दीप्ति का आविर्भाव करता है जिससे वह निरंतर प्रकृति के नित्य नए रहस्यों का अन्वेषी बना रहता है। जीवन संघर्ष के अनुभवों से नए-नए आविष्कार करना मनुष्य की ही क्षमता में है। मनुष्य ने इन अन्वेषणों से अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं की, अपितु इनसे ऊपर उठकर मन की सम्यक संतुष्टि को जीवन का लक्ष्य बनाया है। इसी मनोधारणा ने मनुष्य को प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने-समझने और उनका मानवोचित उपयोग सुलभ करवाने हेतु प्रयत्नशील बनाया है। साथ ही मनुष्य को भूगोल, खगोल तथा सागर के रहस्यों का अन्वेषी बनाया है।

भारतीय कालगणना और नवसंवत्सर भारत की इसी वैज्ञानिक और अन्वेषणकारी प्रतिभा का सिद्धांतरूप है जिससे सूर्य-चंद्र, पृथ्वी-आकाश, नक्षत्र-तारे, ग्रह-उपग्रह, सृष्टि-प्रलय, माह-राशि, व्रत-त्योहार, यज्ञ-हवन, ऋतु-अयन, मंगल-अमंगल, कल्प-युग आदि की सटीक पूर्वगणना की जाती है तथा उनके समाज-जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का प्रामाणिक पूर्वानुमान कर उसी के अनुरूप उत्सव आयोजन अथवा सचेष्ट रहने की योजना की जाती रही है। भारतीय काल गणना के विक्रम संवत् कैलेंडर को यूनानियों ने भी विश्व के अन्य भागों में प्रयुक्त किया है। वेदों में सूर्य के सात घोड़ों से सुसज्जित एक

रथ की कल्पना की गई है, इन सभी सातों घोड़ों का रंग भिन्न है जो सूर्य की किरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सात रंग ही प्रमुखता से हमारी जानकारी में हैं और इन्हीं सात रंगों के सम्मिश्रण से अन्य सभी प्रकार के रंग बनते हैं, इंद्रधनुष में भी यही सात रंग प्रतिभासित होते हैं। भारतीय मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व नक्षत्रों की गतिविधियों और रंग-शास्त्र के ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन किया है।

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत् 2081 (9 अप्रैल 2024) को भारत के सर्वमान्य संवत्सर के रूप में समूचे भारत ने भारतीय नववर्ष उत्सव हर्षोल्लाह से मनाया है। शकों पर विजय प्राप्त करने वाले शकारि सम्राट समुद्रगुप्त के यशस्वी पुत्र और उज्जयनी के विख्यात विद्याप्रेमी सम्राट विक्रमादित्य (वास्तविक नाम चंद्रगुप्त तथा अश्वमेध के अनन्तर 'विक्रमादित्य' की उपाधि ग्रहण की) के नाम से विक्रम संवत् को लागू किया गया। इन्हीं सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नौरत्न अपने-अपने विषय के पारंगत मनीषी थे जिनमें कालिदास (अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंशम, कुमारसंभव), धन्वंतरि (वैद्य चिंतामणि, धनवंतरि निर्घट्ट, चिकित्सा सार-संग्रह - ये सभी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र), वेताल भट्ट (नीति-प्रदीप, वेताल पचीसी), क्षणक (भिक्षाटन, नानार्थ कोश), अमरसिंह (नामलिंगानुशासन-अमरकोश), शंडुकुक (भुवनाभ्युदय), घटखर्पर (घटखर्पर काव्यम, नीतिसार), वराहमिहिर (बृहज्जातक, सूर्यसिद्धांत, बृहत्संहिता, गणक तरंगिणी, योगयात्रा), वररुचि (सदुक्तिकरणाभूत, सुभाषितावलि), शार्ङ्गधर (शार्ङ्गधर संहिता, पत्र कौमुदी, विद्यासुंदर) आदि प्रमुख थे।

### भारत की सर्वोच्च न्याय-प्रणाली

इन दिनों भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ और निर्णय दिए हैं जिनमें एक है - चुनावों में ईवीएम तथा वीवीपैट की पर्चियों के शत-प्रतिशत मिलान की याचिका, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है, साथ ही ईवीएम के स्थान पर मतदान पर्चियों से चुनाव कराए जाने के कुछ राजनीतिक दलों के प्रस्ताव को देश की प्रगति को पीछे ले जाने वाला बताया

है। दूसरा, कुछ अगंभीर राजनेताओं द्वारा विरासत कर के नाम से सामान्य नागरिकों तथा कुछ परिश्रमी नव सम्पत्तिवान् नागरिकों की व्यक्तिगत संपत्ति में से उनकी मृत्यु पर संपत्ति का 50 प्रतिशत सरकार में जमा करवाने के प्रस्ताव को भी नितांत अराजकता फैलाने वाला, वामपंथी विचार माना है। तीसरा, देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को वित्तीय घोटाले के आरोप में जेल में बंद होने के बाद भी जेल से सरकार चलाने व महत्त्वपूर्ण निर्णयों की पत्रावली जेल में मंगवाने को माननीय न्यायालय ने सत्ता व राजनीतिक शक्तियाँ हथियाने की पुरजोर कोशिश माना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसके लिए कड़ी फटकार लगाते हुए इसे 'राष्ट्रीय हित से ऊपर अपना राजनीतिक हित साधना' करार दिया है।

### भाषा-नीति और पाठ्यक्रम

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में वर्ष 2025-2026 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कक्षा 10 तक तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया है, जिनमें दो भारतीय भाषा? होंगी। साथ ही कक्षा 11 व 12 में दो भाषाओं के अध्ययन का प्रावधान किया गया है, जिनमें कम से कम एक भारतीय भाषा होगी, दूसरी भाषा भारतीय अथवा विदेशी हो सकती है। कठिनाई के स्तर से दो बेसिक तथा स्टैंडर्ड भाषाओं का विकल्प देने की योजना भी तैयार की गई है। अभी तक कक्षा 11 व 12 में केवल एक ही भाषा के अध्ययन का प्रावधान था वह भी भारतीय या विदेशी में से कोई एक।

अंत में लोकतंत्र के महापर्व के सकुशल सम्पन्न होने के साथ राष्ट्रोत्थान की मंगलकारी शुभकामना! □

### सम्माननीय सदस्यगण !

शैक्षिक मंथन के जिन सदस्यों की दस वर्षीय सदस्यता पूर्ण हो चुकी है, वे नियमित अंक प्राप्ति हेतु कृपया शीघ्र ही नवीनीकरण करवाने का अनुग्रह करें।



## देश में अमृत काल में निर्धनता उन्मूलन के अप्रतिम प्रयास



**प्रो. राजेश कुमार जांगिड़**  
आचार्य, आर्थिक अध्ययन  
एवं नियोजन विभाग,  
जवाहलाल नेहरू  
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

**नि**र्धनता एक 'मानसिक दशा' नहीं है अपितु एक व्यक्ति जो निर्धन है उसके लिए यह पीड़ादायक है। साथ ही देश में विकास के अभाव को इंगित करती है। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 'वैश्विक निर्धनता उन्मूलन के लिए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण' के लिए ही दिया गया था। निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति 'न्यूनतम स्वीकार्य' जीवन स्तर को प्राप्त करने में असफल रहता है। अभी हाल के वर्षों में भारत में निर्धनता की स्थिति पर रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुमान यह बताते हैं कि भारत में अति निर्धनता लगभग समाप्त हो गई है तथा पिछले एक दशक में बहुआयामी निर्धनता मापन के अनुसार भारत ने निर्धनता उन्मूलन में अद्वितीय

उपलब्धि अर्जित की है। अमृतकाल में भारत में निर्धनता बहुत तेजी से कम हुई है जो सुस्थिर विकास लक्ष्यों के अनुरूप है, समाज के वंचित वर्ग के जीवन में सुधार लाने के साथ ही विश्व आर्थिक संगठनों के लिए आश्चर्य का विषय भी है। निर्धनता में यह तीव्र गिरावट 'सबका साथ- सबका विकास, वाले विकास मॉडल की वास्तविक उपलब्धियों को रेखांकित करने वाला है।

### निर्धनता का मापन

आर्थिक सिद्धांत की दृष्टि से देश में आय के पुनर्वितरण पर विचार करने की दो प्रमुख विधियाँ प्रचलित हैं। एक सापेक्ष आय असमानता की विधि है इसके अंतर्गत यह मापा जाता है कि राष्ट्रीय आय का कितना भाग धनी लोगों की तुलना में निर्धन लोगों को प्राप्त है। दूसरी विधि निरपेक्ष अभाव को मापने की है जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि 'एक न्यूनतम स्वीकार्य आय स्तर' की तुलना में निर्धनों की आय कितनी है। निर्धनता रेखा की परिभाषा

दूसरी विधि से जुड़ी हुई है। निर्धनता रेखा का तात्पर्य उस आय स्तर से है जिसके नीचे की आय निरपेक्ष अभाव का मापन करती है। इसको न्यूनतम जीवन स्तर से परिभाषित किया जाता है। जिसके नीचे के जीवन स्तर को निर्धनता का जीवन स्तर कहा जाता है। निरपेक्ष अभाव को न्यूनतम आय स्तर से मापने में समस्याएँ हैं। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धनों को निशुल्क प्रदत्त वस्तु रूप सहायता (यथा आवास, गैस, पीने के पानी की सुविधा, आदि) को इसमें सम्मिलित नहीं किया। साथ ही आय अर्जन के प्रयास में व्यय इसमें सम्मिलित नहीं होता। इसलिए आय की तुलना में व्यय या उपभोग व्यय के स्तर को निरपेक्ष निर्धनता का बेहतर मापन माना जाता है।

सिद्धांत रूप में निरपेक्ष अभाव की तुलना में सापेक्ष आय असमानता को निर्धनता के मापन के लिए दो कारणों से बेहतर विधि माना जाता है। एक कारण यह है कि किसी समाज में न्यूनतम जीवन स्तर को समाज के अन्य लोगों के जीवन स्तर

की तुलना में ही बेहतर अभिव्यक्त किया जा सकता है। दूसरा कारण यह है कि समाज में कल्याण का स्तर समाज में विद्यमान आय असमानता से विपरीत संबंध में पाया जाता है। उदाहरण के लिए जिन देशों में आय की असमानता अधिक थी वहाँ मृत्यु दर अधिक पाई गई (Deaton, 2003)। भारत में सर्वप्रथम सत्तर के दशक में तत्समय प्रवृत्त योजना आयोग द्वारा निर्धनता को न्यूनतम कैलोरी उपभोग से परिभाषित किया गया। इस परिभाषा में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग को निर्धनता रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। इस परिभाषा की बहुत आलोचना हुई। बाद में न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति के लिए व्यय स्तर के रूप में निर्धनता को परिभाषित किया गया। आजकल दुनिया में निर्धनता के मापन के लिए बहुआयामी निर्धनता सूचकांक प्रचलित है।

### बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

निर्धनता एक बहुआयामी चुनौती है। सभी रूपों व आयाम में निर्धनता निवारण सुस्थिर विकास की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सर्वप्रथम 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट में ए-एफ विधि द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को अपनाया। इस सूचकांक में अभाव के स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर के तीन प्रमुख आयाम को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत कुल दस संकेतांक हैं। पोषण एवं बाल व किशोर मृत्यु स्वास्थ्य से संबंधित संकेतांक हैं। विद्यालय के वर्ष व विद्यालय में उपस्थित के दो संकेतांक शिक्षा आयाम के अंतर्गत हैं। कुकिंग फ्यूल, स्वच्छता, पीने का पानी, आवास, बिजली तथा संपत्ति जीवन स्तर आयाम के संकेतांक हैं। नीति आयोग ने अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में यूएनडीपी के 10 संकेतकों के अलावा मातृत्व स्वास्थ्य एवं बैंक खाता दो और



संकेतांक शामिल कर भारत के संदर्भ में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की गणना की है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निर्धनता अनुपात (कुल जनसंख्या से निर्धन लोगों का प्रतिशत) के साथ-साथ निर्धनता की गहनता (निर्धनों में निर्धनता की स्थिति) का भी मापन करता है।

तेज गति से आर्थिक विकास देश में सभी के लिए आय सृजन के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ सरकार के जन कल्याण पर अधिक प्रयास की क्षमता को बढ़ाता है। पिछले एक दशक में भारत आर्थिक विकास के कारण 'सबसे कमजोर पाँच अर्थव्यवस्था' समूह से निकलकर 'सबसे बड़ी पाँच अर्थव्यवस्थाओं' के समूह में सम्मिलित हो गया है। निर्धनता निवारण के अध्ययन यह इंगित करते हैं कि अमृतकाल में भारत में अति निर्धनता लगभग समाप्त हो गई है। साथ ही पिछले 9 वर्षों में (इसमें कोविड-19 संकट की अवधि भी सम्मिलित है) भारत में 24.92 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं।

### भारत में निर्धनता उन्मूलन की स्थिति

पिछले एक दशक में भारत में निर्धनता निवारण की स्थिति के संबंध में तीन प्रमुख रिपोर्ट हैं। इनमें ब्रुकिंग्स रिपोर्ट, वर्ल्ड पावर्टी वॉच रिपोर्ट तथा नीति आयोग की रिपोर्ट है। इन तीनों अध्ययनों में एक राय है कि भारत ने पिछले एक दशक में निर्धनता निवारण में अद्भुत व आश्चर्यजनक उपलब्धि अर्जित की है।

(1) नीति आयोग का अध्ययन : नीति आयोग ने अपने अध्ययन 'मल्टीडाइमेंशनल पावर्टी इन इंडिया सिंस 2005-06' में भारत में वर्ष 2013-14 से 2022-23 के बीच निर्धनता के सभी आयामों में उल्लेखनीय कमी के लिए सरकार की महत्वपूर्ण पहलों को श्रेय दिया है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त अवधि (2013-14 से 2022-23) में भारत में बहुआयामी गरीबी 29.17 प्रतिशत से घटकर 11.28 प्रतिशत हो गई है। यह 17.59 प्रतिशत की गिरावट है। उक्त 9 वर्ष की अवधि में देश में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता की रेखा से बाहर आ चुके हैं। अध्ययन के अनुसार देश में वर्ष 2015-16 से 2019-21 के मध्य प्रतिवर्ष 10.66 प्रतिशत की दर से बहुआयामी निर्धनता में कमी हुई है। यह बहु आयामी निर्धनता में कमी 2005-06 से 2015-16 के मध्य 7.69 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिक थी। पिछले 9 वर्षों में बहु आयामी निर्धनता में तीव्र गिरावट सरकार की समाज



के सबसे कमजोर वर्ग के जीवन में उत्थान के लिए सतत प्रतिबद्धता में समर्पण को व्यक्त करता है। उक्त अवधि में बहु आयामी निर्धनता निवारण में सर्वाधिक प्रभावी परिणाम उन राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा व बिहार) में हुए जहाँ बहुआयामी निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव था। अध्ययन के अनुसार निर्धनता निवारण स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर के तीनों आयाम में देखी गई है। गरीबों का प्रतिशत कम होने के साथ ही गरीबों में भी गरीबी कम हुई है। उक्त अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी निर्धनता निवारण शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक तेजी से देखी गई है। उक्त अध्ययन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के समकों का प्रयोग करते हुए संपन्न किया गया है। यह अध्ययन यह भी व्यक्त करता है कि भारत बहु आयामी निर्धनता को 2030 तक आधे स्तर पर लाने के सुस्थिर विकास लक्ष्य को समय से बहुत पहले प्राप्त करने में सफल होगा। आयोग के अध्ययन में भारत के पिछले 9 वर्षों के बहुआयामी निर्धनता निवारण की अद्वितीय उपलब्धियों के लिए सरकार की योजनाओं यथा पोषण अभियान, विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना), मातृत्व स्वास्थ्य, उज्वला योजना, सौभाग्य (ग्रामीण विद्युतीकरण), स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना

एवं सुरक्षित आवास के प्रभावी क्रियान्वयन को श्रेय दिया गया है।

**(2) बुकिंग्स अध्ययन :** इस अध्ययन में संशोधित मिश्रित याददाश्त अवधि विधि से उपभोग व्यय समकों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में निर्धनता का अनुमान दो निर्धनता रेखा परिभाषाओं से किया गया है। एक परिभाषा में डॉलर 1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन व्यय को आधार मानकर निर्धनता अनुपात की गणना की गई है। डॉलर 1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रय शक्ति समता को अति निर्धनता रेखा माना जाता है। दूसरी परिभाषा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रय शक्ति क्षमता डॉलर 3.02 को निर्धनता रेखा मानकर अनुमान दिए गए हैं। दूसरी परिभाषा को विश्व बैंक ने निम्न मध्यम आय वर्ग देश के लिए निर्धनता रेखा माना है। भारत में निर्धनता पर बुकिंग्स अध्ययन बताता है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में वर्ष 2011 के बाद असमानता में अभूतपूर्व गिरावट देखी गई है। डॉलर 1.9 की निर्धनता रेखा के अनुसार भारत में अति निर्धनता लगभग समाप्त हो गई है। वर्ष 2022 में निर्धनता अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र में एक प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। डॉलर 3.2 की निर्धनता रेखा के अनुसार निर्धनता अनुपात 2011 के 53.6 प्रतिशत से गिरकर 2022 में 20.8 प्रतिशत रह गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस निर्धनता अनुमान की गणना

में दो तिहाई जनसंख्या को दिया जा रहा निःशुल्क भोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर सरकार के प्रयासों को शामिल नहीं किया गया है। डॉलर 3.2 की निर्धनता रेखा के अनुसार निर्धनता अनुमान में गिरावट का कारण पिछले एक दशक में हुआ समावेशी विकास है। डॉलर 3.2 की निर्धनता रेखा के अनुसार निर्धनता अनुपात में कमी यह इंगित करती है कि देश ने जो पिछले 11 वर्षों में अर्जित किया वह उससे पहले के 30 वर्षों में किए गए प्रयासों के समान है। अर्थात् देश की निर्धनता निवारण की पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियाँ उससे पहले की 30 वर्षों की उपलब्धियों के समान हैं। अध्ययन में यह भी इंगित किया गया है कि पिछले 11 वर्षों में निर्धनता निवारण में सरकार की कल्याणकारी व आय पुनर्वतरण की नीतियों ने सबसे बड़ी भूमिका निर्वाह की है। शौचालय निर्माण, उज्वला योजना, सार्वभौमिक बिजली उपलब्धता और नल से जल जैसी नीतियों ने देश में निर्धनता निवारण में अद्वितीय भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए वर्ष 2019 में ग्रामीण क्षेत्र में 16.5 प्रतिशत नल से जल आपूर्ति थी जो 2023 में 74.7 प्रतिशत क्षेत्र में हो गई है।

**(3) वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक अनुमान :** वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के अध्ययन अनुमान के अनुसार भारत में अति निर्धनता अनुपात तीन प्रतिशत से भी नीचे है। यह अनुमान वर्ष 2022-23 के परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इस अनुमान में निर्धनता रेखा डॉलर 2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय की परिभाषा पर आधारित है।

**आय गारंटी व नैतिक जोखिम :** यदा कदा निर्धनता निवारण के लिए आय गारंटी की बात की जाती है (भारत के संदर्भ में कभी बहतर हजार रुपए कभी 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष)। यहाँ आर्थिक सिद्धांत की दृष्टि से निर्धनता निवारण के लिए न्यूनतम आय गारंटी नीति का विश्लेषण प्रासंगिक





है। न्यूनतम आय गारंटी में एक निर्धनता रेखा परिभाषित की जाती है तथा जिन की आय इस निर्धनता रेखा से कम है उनकी आय में इस अंतराल की पूर्ति नकद हस्तांतरण के द्वारा की जाती है। न्यूनतम आय गारंटी नीति द्वारा निर्धनता निवारण में नैतिक जोखिम (moral hazard) निहित होता है। नैतिक जोखिम यह निहित होता है कि नकद आय हस्तांतरण के कारण निर्धनता से बाहर निकलने के लिए श्रम बढ़ाने के प्रयास कमजोर हो जाते हैं। आर्थिक सिद्धांत में जब कार्य करने (श्रम के घंटे) अनुकूलतम करने की बात होती है तो समय उपयोग के दो विकल्प उपस्थित होते हैं। व्यक्ति की आय अथवा उपभोग व्यय तथा आराम का समय। उपभोग व्यय बढ़ता है तो आराम का समय कम होता है इसके विपरीत आराम का समय बढ़ाने पर उपभोग व्यय में कमी करना पड़ती है। उपभोक्ता कम संतुष्टि की तुलना में अधिक संतुष्टि को अधिमान देता है। कम आय की तुलना में अधिक आय तथा कम आराम की तुलना में अधिक आराम को अधिमान देता है। न्यूनतम आय गारंटी योजना द्वारा निर्धनता

निवारण की नीति की स्थिति में व्यक्ति के पास बिना अधिक श्रम के प्रयास किए अधिक आय एवं अधिक आराम के साथ उच्च संतुष्टि का विकल्प उपस्थित होता है। आर्थिक सिद्धांत में विवेकशील उपभोक्ता होने के कारण व्यक्ति इस उच्च संतुष्टि स्तर के विकल्प को अधिमान देकर चयन करता है जो व्यक्ति के निर्धनता से बाहर निकलने के लिए श्रम के घंटों को बढ़ाने के प्रयास को कमजोर करता है। कार्य के घंटों में यह कमी अर्थव्यवस्था में श्रम की कुल मात्रा को भी कम कर देती है। इसलिए पब्लिक पॉलिसी सिद्धांत की दृष्टि से आय गारंटी योजना अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। हालांकि व्यक्तिगत एवं राजनीतिक लाभ की दृष्टि से यह आकर्षक हो सकती है।

### निष्कर्ष

तेज गति से आर्थिक विकास देश में सभी के लिए आय सृजन के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ सरकार के जन कल्याण पर अधिक प्रयास की क्षमता को बढ़ाता है। पिछले एक दशक में भारत आर्थिक विकास के कारण 'सबसे कमजोर पाँच

अर्थव्यवस्था' समूह से निकलकर 'सबसे बड़ी पाँच अर्थव्यवस्थाओं' के समूह में सम्मिलित हो गया है। निर्धनता निवारण के अध्ययन यह इंगित करते हैं कि अमृतकाल में भारत में अति निर्धनता लगभग समाप्त हो गई है। साथ ही पिछले 9 वर्षों में (इसमें कोविड-19 संकट की अवधि भी सम्मिलित है) भारत में 24.92 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। इस अद्वितीय उपलब्धि के लिए सरकार के जन कल्याण के लिए संकल्प एवं प्रतिबद्धता को उत्तरदायी कहा जाता है। तीव्र गति से निर्धनता निवारण सरकार के 'सबका साथ सबका विकास' वाले विकास मॉडल के सफल कार्यकरण को इंगित करता है। इस अवधि में निर्धनता का प्रभाव जिन राज्यों में अधिक था उन राज्यों में अधिक तेजी से निर्धनता में कमी हुई है। उल्लेखनीय है कि इस अवधि में भारत में आय की असमानता भी कम हुई है। निर्धनता मापन की दोनों विधियों (सापेक्ष निर्धनता व निरपेक्ष निर्धनता) की दृष्टि से भारत में 2013-14 से 2022-23 के मध्य की अवधि में निर्धनता निवारण में अप्रतिम सफल प्रयास हुए हैं। □



## विकेंद्रीकरण : अमृतकाल में भारत में रोजगार वृद्धि युक्त विकास की रणनीति



**प्रो. सुशील कुमार बिस्मू**

क्षेत्रीय निदेशक, अजमेर  
उच्च शिक्षा विभाग,  
राजस्थान सरकार

### रोजगार विहीन विकास

पंडित उपाध्याय के अनुसार अर्थव्यवस्था में कृषि पर भार को कम करने और रोजगार प्रदान करने में उद्योगों का विशेष महत्व होता है। भारत के आर्थिक विकास की

महत्वपूर्ण विशेषता रोजगार में अपेक्षाकृत कम वृद्धि है, जिसे अर्थशास्त्री रोजगार विहीन विकास कहते हैं। भारत की नियोजन अवधि में सकल घरेलू उत्पाद एवं रोजगार में वृद्धि की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है -

तालिका 1 - भारत की आर्थिक वृद्धि में रोजगार की अल्पता

क्र.	समयावधि (वर्ष)	जीडीपी वृद्धि दर	रोजगार वृद्धि दर	रोजगार रहित विकास
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(4)=(5)
1.	1951-56	3.6	0.39	3.21
2.	1956-61	4.2	0.85	3.25
3.	1961-66	2.8	2.03	0.77
4.	1967-69	3.9	2.10	1.80
5.	1969-74	3.3	1.99	1.31
6.	1974-79	4.8	1.84	3.04
7.	1980-85	5.7	1.73	4.03
8.	1985-90	5.8	1.89	3.91
9.	1990-92	3.4	1.50	1.90
10.	1997-2000	6.1	0.98	5.13
11.	2005-10	8.7	0.28	8.42
12.	2021-22	8.7	-	-

(स्रोत - एनसीईआरटी और आर्थिक समीक्षा)

**स्व**तंत्रता के पश्चात यद्यपि भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के संदर्भ में कई प्रयत्न किए गए, तथापि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार की अल्पता प्रमुख समस्या बनी हुई है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों की अमृत वेला में भारत में रोजगार वृद्धि युक्त विकास के लिए हमें अंतर्निहित प्रौद्योगिकी एवं विकेंद्रीकरण की उस रणनीति को गहराई से अपनाना होगा जो भारत के भविष्य का स्वप्न देखने वाले एकात्म मानववाद की प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विकसित किया है।



तालिका से स्पष्ट है कि भारत में रोजगार की वृद्धि दर सदैव कम ही रही है, पिछले दो दशकों में तो जीडीपी वृद्धि दर और रोजगार वृद्धि दर के मध्य अंतर बहुत बढ़ गया है। जब आर्थिक वृद्धि रोजगार सर्जन करने में सक्षम नहीं होती है तो गरीबी और असमानता की समस्याएँ विराट रूप ले लेती हैं।

समकालीन भारत में रोजगार विहीन विकास की इस विकट स्थिति में दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों का विशेष महत्त्व हो जाता है, क्योंकि -

1. उपाध्याय उद्योग नीति के व्यापक सामाजिक उद्देश्यों को प्रमुखता देते हैं। इन सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संरक्षण को उपयोगी उपकरण स्वीकार करते हैं।

2. उद्योगों का स्वाभाविक विकास उपाध्याय के अनुसार जो उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के अनुरूप ना होकर ऊपर से लादे हुए हैं वे रोजगार में स्वाभाविक विकास नहीं कर पाते हैं।

3. उपाध्याय का विचार है कि भारत में औद्योगिक नीति का विचार करते हुए पहले से विद्यमान संगठित एवं असंगठित क्षेत्र तथा विकसित एवं अर्ध विकसित सभी प्रकार के उद्योगों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए।

**इंडोजीनीयस प्रौद्योगिकी विकास** - उपाध्याय (1958) के अनुसार 'देश की उपलब्धि उपादानों के अनुरूप उत्पादन प्रक्रिया का निर्धारण एवं विकास हमारी सबसे बड़ी समस्या है।' इस संबंध में वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सभापति एमएस



ठक्कर द्वारा विकासात्मक आयात के साथ-साथ देशज प्रौद्योगिकी ढाँचे के विकास के पक्षधर थे।

उपाध्याय मशीनीकरण के विरुद्ध नहीं हैं वे लघु उद्योग एवं आधुनिक उत्पादन पद्धति को औद्योगिक नीति में प्रमुखता देने की संस्तुति करते हैं।

उद्योगों के विकास का क्रम, जो 'वर्तमान में (1) मूल उद्योग, (2) उत्पादन वस्तु उद्योग एवं (3) उपभोग वस्तु उद्योग' के रूप में चला आ रहा है, उपाध्याय इसे उलट कर (1) उपभोग वस्तु (2) उत्पादन वस्तु (3) मूल उद्योग का क्रम श्रेष्ठ मानते हैं। इसके पीछे रोजगार वृद्धि ही प्रमुख आधार है।

उद्योगों को वरीयता, उपाध्याय सामाजिक मूल्यों, बेरोजगारी, लंबी

गर्भावधि, पूंजी के गुणक (Multiplier) प्रभाव की न्यूनता, कृषि से निकट संबंध ना होने और बिचौलियों के प्रादुर्भाव के कारण वृहद उद्योगों पर लघु उद्योगों को वरीयता देते हैं। ताकि क्षेत्रीय असंतुलन में कमी आए, समाज में आर्थिक विषमता की प्रवृत्ति कम हो, विकेंद्रीकरण एवं रोजगार युक्त विकास को बढ़ावा मिल सके।

उद्योगों के स्वामित्व के विषय में उपाध्याय का विचार है कि 'महात्मा गांधी और गुरु गोलवलकर के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार छोटे-छोटे उद्योगों को व्यक्तिगत स्वामित्व में ही बनाए रखना चाहिए' ताकि रोजगार का आत्मस्फुरित विकास हो।

दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों का व्यावहारिक उपयोग, भारत में रोजगार विहीन विकास को रोजगार युक्त विकास की ओर मोड़ने में किया जा सकता है।

**विनिर्माण क्षेत्र एवं आत्मनिर्भर भारत** -

आज भारत विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के योगदान का विश्लेषण करने पर यह

तालिका 2 - विनिर्माण क्षेत्र में भारत और चीन की तुलना

क्र.स.	विनिर्माण क्षेत्र संबंधी तथ्य	चीन	भारत
1.	श्रम बाजार कुशलता (138 देशों में स्थिति)	34 वाँ	99 वाँ
2.	विनिर्माण का जीडीपी से अनुपात	31.8 %	12.9 %
3.	अंतरराष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग निर्यात में हिस्सा	17.5 %	1.6 %
4.	वैश्विक विनिर्माण रोजगार में हिस्सेदारी	34 %	5.8 %

निष्कर्ष निकलता है कि नियोजन के प्रारंभिक दशकों में प्राथमिक क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका (Lead Role) थी जो कि वर्तमान में सेवा क्षेत्र (2020-21 में 53.8 प्रतिशत) ने ले लिया है। इस प्रकार भारत में विनिर्माण क्षेत्र पूरे नियोजन काल में उपेक्षित रहा। एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने में प्रयासरत भारत के विनिर्माण क्षेत्र की चीन से तुलना करना समीचीन हो जाता है -

आज चीन विश्व का विनिर्माण केंद्र बन गया है जबकि भारत एक दृष्टि में बहुत पीछे है। भारत को आत्मनिर्भर एवं विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता प्रकट होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति में दीनदयाल उपाध्याय के औद्योगिक नीति संबंधी विचारों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। क्योंकि उपाध्याय ने अपनी पुस्तक भारतीय अर्थ नीति विकास की एक दिशा के अध्याय 6 उद्योग में मत व्यक्त किया था कि “अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विशेषकर मंदी के दिनों में उसे भारी संकटों का सामना करना पड़ा। प्राचीन शास्त्रकारों ने वाणिज्य, शिल्प एवं उद्योगों के संबंध में यह लिखा है कि उन्हें अपरमात्रिक होना चाहिए।” इसके साथ ही उन्होंने उद्योगों के स्वाभाविक विकास, वरीयता क्रम एवं विकास क्रम में विनिर्माण को महत्व दिया है।

तालिका 4 - भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का योगदान

क्र.स.	तथ्य	एमएसएमई का योगदान 2018-19
1.	राष्ट्रीय आय	33.50 प्रतिशत
2.	रोजगार	11.10 करोड़
3.	निर्यात	48.10 प्रतिशत

(स्रोत - सी एस ओ, एन एस एस 73 वाँ दौर, एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट)

### विकेंद्रीकरण एवं लघु उद्योग MSME

भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र एवं जनाधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, उसमें लघु उद्योगों एवं विकेंद्रीकरण का कई कारणों से विशेष महत्व है। उपाध्याय के अनुसार “औद्योगीकरण के लिए आवश्यक उपादान और उनका पूरक था तथा प्राथमिकताओं का विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुँचते हैं कि भारत के लिए छोटे-छोटे उद्योग ही सर्वाधिक उपयुक्त हैं।”

इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करके देश के सभी क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करने के लिए विकेंद्रीकरण एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। महात्मा गांधी एवं अन्य भारतीय विचारकों के समान ही दीनदयाल उपाध्याय ने भी विकेंद्रीकरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। विकेंद्रीकरण के द्वारा स्थानीय संसाधनों - कच्चे माल एवं श्रम, का उपयोग होने से समावेशी विकास के मार्ग खुलते हैं

और आर्थिक विषमता एवं वंचित वर्गों में कमी आती है। भारत के नियोजन काल में जिस टपकन प्रभाव (Trickle down effect) की आशा की गई थी जो कि फलीभूत नहीं हुई, उस आर्थिक विकास के टपकन प्रभाव को उत्पन्न करने में विकेंद्रीकरण एवं लघु उद्योग विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं।

भारतीय अर्थ नीति में पिछले कुछ वर्षों में एमएसएमई पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया जा रहा है। भारत की जीडीपी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के सकल मूल्य वर्धित का हिस्सा निरंतर बढ़ता जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा कोविड-19 एवं लॉकडाउन की परिस्थितियों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई सेक्टर पर बहुत बल दिया गया है। एमएसएमई संबंधी परिभाषाओं में भी युगानुकूल संशोधन किए गए हैं। एमएसएमई क्षेत्र कृषि एवं उद्योग क्षेत्र के मध्य संक्रमण का क्षेत्र होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र के उपर्युक्त योगदान को देखते हुए दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के अनुरूप औद्योगिक रणनीति में अपेक्षित संशोधन किया जाना चाहिए। ऐसा करके रोजगार, आत्मनिर्भरता एवं अन्य आर्थिक क्षेत्रों में एमएसएमई के योगदान को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही राष्ट्रीय आय में द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग) के योगदान को भी बढ़ाया जा सकता है। □

तालिका 3 - भारत की जीडीपी में एमएसएमई के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का हिस्सा

क्र.स.	वर्ष	एमएसएमई के जी.वी.ए की वृद्धि दर	जीडीपी में योगदान
1.	2014-15	-	31.80 प्रतिशत
2.	2015-16	10.97 प्रतिशत	32.28 प्रतिशत
3.	2016-17	10.90 प्रतिशत	32.24 प्रतिशत
4.	2017-18	12.98 प्रतिशत	32.79 प्रतिशत
5.	2018-19	12.88 प्रतिशत	33.50 प्रतिशत

(स्रोत एमएसएमई मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 भारत सरकार)

# अमृतकाल के विकासमान भारत में कौशल विकास की भूमिका



**प्रो. राजेश कुमार जोशी**

आचार्य, संस्कृत विभाग  
श्री गोविन्द गुरु राजकीय  
महाविद्यालय बांसवाड़ा  
(राजस्थान)

**आ**धुनिक विज्ञान-प्रौद्योगिकी से मानवीय सुख-सुविधाओं में यद्यपि आशातीत वृद्धि हुई है किन्तु इससे पर्यावरण के भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों आयाम बुरी तरह से असन्तुलित हुए हैं। कृत्रिम वातावरण की क्षमता को विकसित करके हम इस सृष्टि के किसी अंश में स्वयं संचालक तो अवश्य बन गये हैं किन्तु इसी व्यवहार के कारण सृष्टि विरोधी भी हो गए हैं। इस बीच बढ़ रहे वैश्विक युद्धों, पिघलते हिमशैलों, दरकते पहाड़ों और वैश्विक भूतापीकरण से ऊपजे जलवायु परिवर्तन आदि की आहत से भावी पीढ़ियों के सामने भयंकर आपदाएं सुरसा के समान मुँह बाए खड़ी हैं। जीव सृष्टि के सामने अस्तित्व

की समस्या खड़ी हो गई है। दोष विज्ञान प्रौद्योगिकी का ही नहीं है, प्रत्युत शाश्वत जीवन मूल्यों के वृहत्तर परिप्रेक्ष्य को भुला-बैठने का भी है।

जीवन के अर्थ और उसकी चुनौतियों को समझने, चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल और उसका ज्ञान बाँटने, इस प्रक्रिया में विविध कौशल निर्माण के माध्यम से स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने, सफल, जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक बनने में सहायता करना ही कौशल विकास का प्रमुख ध्येय है जो अमृतकाल के विकासमान भारत के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व के लिए उपादेय होगा।

समूह 20 के शिखर सम्मेलन, 2023 की अध्यक्षता में भारत ने धारणक्षम विकास का रोडमैप प्रस्तुत कर जीव सृष्टि के संरक्षण और सम्वर्द्धन का अपना संकल्प दोहराया है। किन्तु सम्पूर्ण विश्व में कौशल विकास के समुचित पल्लवन की आवश्यकता है। सुखी और

आरामदेह जीवनशैली के कारण ऊपजे संकट से निपटने में कौशल निर्माण ही वह कड़ी है जो समस्याओं से निजात दिलाकर सतत विकास को प्रवहमान रख सकती है।

कौशल विकास में प्राच्य भारतीय दृष्टिकोण से जुड़े सन्दर्भ देते हुए उदात्त भाव रखने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत आलेख कौशल निर्माण के प्रमुख घटकों का नूतन और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्लेषण करने का एक विनम्र प्रयास है। विभिन्न कौशलों के विकास और उन्नयन की दिशा में हमारे प्राच्य सन्दर्भ आधुनिक मानव सभ्यता के लिये समस्याओं के समाधान में महती भूमिका निर्वहन कर सकते हैं, वे प्रमुख कौशल निम्नानुसार हैं -

**1. जीवन कौशल** - इस कौशल में जीवन से संघर्ष अथवा मुकाबला करने का अर्थ और स्पष्टीकरण, संघर्ष के सकारात्मक और नकारात्मक तंत्र, संघर्ष के प्रकार, संघर्ष करने के कौशल और संघर्ष



करने की रणनीतियाँ समाहित हैं। जीवन में समय की महत्ता, समय के विवेकपूर्ण उपयोग और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वस्थ, स्वीकार्य ईमानदार तंत्र विकसित करना कहीं श्रेष्ठ है। हितोपदेश मित्रलाभ के एक श्लोक में कहा गया है कि कुशल जीवन जीने में अनेक बाधाएँ पार करनी होती हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल में उठते ही किसी भी अनहोनी अथवा भय से निपटने की युक्ति हमेशा पास में होनी चाहिए। क्योंकि मृत्यु, बीमारी और शोक (दुर्घटना) में से कोई कभी भी टपक सकता है -

**उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं**

**महद्भयमुपस्थितम्।**

**मरणव्याधिशोकानां**

**किमद्य निपतिष्यति?।।**

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह काव्य पंक्तियाँ जीवन कौशल के लिये वरदान रूप हैं -

**बाधाएँ आती हैं आएँ,**

**घिरें प्रलय की घोर घटाएँ**

**पाँवों के नीचे अंगारे,**

**सिर पर बरसें यदि ज्वालाएँ,**

**निज हाथों से हँसते-हँसते,**

**आग लगाकर जलना होगा।**

**कदम मिलाकर चलना होगा।।**

**2. आत्मसम्मान** - आत्मसम्मान की अवधारणा में यह बात प्रमुखता से आती है कि किसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान क्यों जरूरी है और सकारात्मक आत्म विकास में यह उन्हें कैसे सहायता कर सकता है? उन्हें स्वयं को वैसे ही स्वीकार करना सिखाया जाता है जैसे वे हैं, उनकी सभी शक्तियों और कमजोरियों के साथ जिससे यह उन्हें एक पूर्ण और समृद्ध व्यक्ति, पूरी तरह से जीवित और मानव के रूप में जीने में मदद कर सके। महाकवि भारवि कृत किरातार्जुनीयम् महाकाव्य की दो सूक्तियाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं - 'वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः' अर्थात् जो व्यक्ति सोच-समझकर

कार्य करता है, गुणों से आकृष्ट होने वाली सम्पत्तियाँ स्वयं ही उसका वरण (चुनाव) करती है। 'जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समा गतिः' अर्थात् स्वाभिमान-रहित व्यक्ति और तिनके की स्थिति एक जैसी होती है।

### 3. सकारात्मक सोच -

सकारात्मकता जीवन की धारणा को सही और लक्ष्योन्मुखी बनाने में मदद करती है। इस कौशल का प्रमुख उद्देश्य है - जीवन में अच्छाई पर जोर देना, नरम और कोमल दिमाग वाले से कठोर दिमाग वाले व्यक्ति में तथा कमजोर, नकारात्मक व्यक्ति से ताकतवर व्यक्ति में बदलना। नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिये आत्मा की शक्ति को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इस हेतु हमारी प्राचीन ध्यान साधना बेहद कारगर है, जिसे कुण्डलिनी जागरण, शक्ति जागरण, षट्चक्र साधना और त्रिपुरसुन्दरी ध्यान आदि अनेक नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद सम्मत शरीर की 72 हजार नस-नाडियों के रक्त प्रवाह को ठीक करने, स्वयं के भीतरी ऊर्जा-स्तर को ऊँचा उठाने के लिये षट्चक्रों के बीज मन्त्रों से उत्पन्न तरंगों सकारात्मकता को बढ़ाने में अत्यन्त उपादेय हैं।

'ध्यान' भारतवर्ष की संसार को बहुत बड़ी देन है, जिसमें मन्त्र, श्वास और मन की एकाग्रता पर जोर दिया जाता है। ध्यान साधना के अनुसार जब किसी भी मन्त्र की ध्वनि हमारे शरीर में उतरती है तो कुछ सूक्ष्म तरंगें वाईब्रेट होकर हमारी सकारात्मकता को बढ़ा देती हैं। मूलाधार चक्र से प्रारम्भ होकर आज्ञाचक्र तक के छः चक्रों अथवा ग्रन्थि स्थलों के क्रमिक और दैनिक ध्यान से हम एक परिपूर्ण व्यक्तित्व बन सकते हैं। अवसाद को दूर करके आत्मसाक्षात्कार कराने वाली ध्यान साधना अश्रुत को श्रुत और अदृष्ट को दृष्ट में बदल सकती है। इसके महत्त्व के विषय में श्रीमद्भगद्गीता के द्वितीय अध्याय का यह अन्तिम श्लोक महत्त्वपूर्ण है -

**एषा ब्राह्मी स्थितिः**

**पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति।**

**स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि**

**ब्रह्मनिर्वाणमुच्छति।।**

**4. प्रेरणा और आत्म-बोध** - यह कौशल एक सार्थक लक्ष्य की दिशा में व्यक्ति के प्रयासों को ऊर्जावान बनाने और उसे निर्देशित करने से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रेरणा को बढ़ाने के लिये अधिक आत्म-निर्देशित बनना शामिल है, जो व्यक्ति की आवश्यकताओं, इच्छाओं और आकाँक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करना है। सपनों को सच में बदलने के लिये केवल प्रेरणा नहीं अन्तर्प्रेरणा की आवश्यकता होती है। बल नहीं अन्तर्बल की जरूरत होती है। महाकवि माघ ने शिशुपालवध के द्वितीय सर्ग में कहा है कि साधारण अल्पबुद्धि लोग छोटे कार्य का आरम्भ करते हुए भी बाधाएँ आने पर व्याकुल हो जाते हैं जबकि विशिष्ट अर्थात् सुशिक्षित बुद्धि वाले मनुष्य बड़े-बड़े कार्यों का आरम्भ करके भी निश्चिन्त रहते हैं किंवा सफलता प्राप्त करते हैं -

**आरम्भतेऽल्पमेवाज्ञाः कामं**

**व्यग्राः भवन्ति च।**

**महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति**

**च निराकुलाः।।**

**5. लक्ष्य निर्धारण** - यह कौशल विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों, व्यक्तिगत लक्ष्यों की खोज और उन तक पहुँचने के प्रयास के महत्त्व से परिचित कराता है। लक्ष्य एक समय सीमा और एक कार्य योजना वाले सपने हैं। लक्ष्य योग्य या अयोग्य हो सकते हैं। लक्ष्य चाहत नहीं, जुनून होता है जो स्वप्न को यथार्थ में बदल देता है। इस अनुष्ठान में आलस्य बाधक है और शरीर में रहकर एक भयंकर शत्रु का काम करता है जबकि उद्यम (परिश्रम) बन्धु बनकर ऐसे सहायक का काम करता है, जिसको अपनाकर व्यक्ति कभी दुःखी नहीं होता है। महाकवि भर्तृहरि ने नीतिशतकम् की कर्म पद्धति के पहले ही श्लोक में कहा है -

आलस्यं हि मनुष्याणां  
शरीरस्थो महान् रिपुः ।  
नास्त्युद्यमसमो बन्धुः  
कृत्वा यं नावसीदति ॥

6. समस्या समाधान - समस्याओं को उनके पिछले निर्णयों के संदर्भ में देखने में मदद करना, ऐसे निर्णयों के परिणामों की जाँच करना और फिर अधिक संतोषजनक वैकल्पिक परिणाम चुनना समस्या समाधान कौशल में निहित है। इतिहास यही सिखाता है कि प्रत्येक समस्या का एक सीमित जीवन काल होता है। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। जीवन में आने वाली परेशानियाँ भी स्थायी न होकर सीमित कालखण्ड तक रहती हैं। तूफान सदैव सूरज को रास्ता देते हैं। सर्दी हमेशा वसन्त ऋतु में बदल जाती है इसलिए वैयक्तिक तूफान भी टल जायेगा, यह मानकर समस्या के उचित समाधान हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस सम्बन्ध में भर्तृहरि नीतिशतकम् के एक श्लोक का सन्दर्भ देना उपयुक्त होगा -

रत्नैर्माहैस्तुतुर्षु न देवाः,  
न भेजिरे भीमवीषेण भीतिम्।  
सुधां विना न प्रययुर्विरामः  
न निश्चिन्ताथार्ताद् विरमन्ति धीराः ॥

अर्थात् समुद्र मंथन से निकले बहुमूल्य रत्नों को पाकर भी देवता सन्तुष्ट नहीं हुए, न ही भयंकर हलाहल विष को पाकर विचलित हुए। अमृत प्राप्ति तक उन्होंने विराम नहीं लिया क्योंकि धीर पुरुष समस्याएँ आ जाने पर भी अपने निर्धारित लक्ष्य से कभी विरत नहीं होते हैं।

7. निर्णय क्षमता - समस्याओं को अपने निर्णयों के संदर्भ में देखना चाहिए। घटनाओं और परिस्थितियों के परिणामों से जोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं है। निर्णय क्षमता का कौशल यह समझने में मदद करता है कि व्यक्तिगत विकास के संबंध में निर्णय ही विशेष रूप से उत्तरदायी होते हैं। पंचतन्त्र के अनुसार जिसके पास स्वयं की

जीवन कौशल में जीवन से संघर्ष अथवा मुकाबला करने का अर्थ और स्पष्टीकरण, संघर्ष के सकारात्मक और नकारात्मक तंत्र, संघर्ष के प्रकार, संघर्ष करने के कौशल और संघर्ष करने की रणनीतियाँ समाहित हैं।  
अवसाद को दूर करके आत्मसाक्षात्कार कराने वाली ध्यान साधना अश्रुत को श्रुत और अदृष्ट को दृष्ट में बदल सकती है। इसके महत्त्व के विषय में श्रीमद्भगद्गीता के द्वितीय अध्याय का यह अन्तिम श्लोक महत्त्वपूर्ण है -  
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥

विवेकबुद्धि नहीं होती तो शास्त्र उसका क्या कर सकता है ? अन्धे मनुष्य के लिये दर्पण का कोई औचित्य नहीं होता -

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा  
शास्त्रं तस्य करोति किम् ।  
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः  
किं करिष्यति ? ॥

8. समय प्रबंधन - इसका प्रमुख उद्देश्य समय की महत्ता बताना है। समय का यदि प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए तो जीवन के महान लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिल सकती है। समय की पाबन्दी एक ऐसी आदत है जिसे विकसित किया जा सकता है। आदान और प्रदान से जुड़ा जो भी कार्य करना होता है, उसे अपेक्षित समय पर और बिना देरी किये करना चाहिए। यदि वह निर्धारित समय पर नहीं होता है तो उस कार्य की प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। हितोपदेश कहता है -

आदानस्य प्रदानस्य  
कर्तव्यस्य च कर्मणि ।  
क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः  
पिबति तद्रसम् ॥

9. तनाव प्रबंधन - तनाव मानव जाति को आधुनिक जीवन शैली के परिणामस्वरूप मिलने वाला एक अप्राकृतिक उपहार है। तनाव का प्रबन्धन कैसे किया जाए ? यही इस कौशल का प्रतिपाद्य विषय है। उत्पन्न होने वाली तीव्र भावनाओं को अधिक उचित तरीके से शामिल करना, समग्र तनाव की स्थितियों को संशोधित करने और शारीरिक चुनौतियों का सामना करने, समस्याओं को हल करने और लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए तनाव के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना, निर्देशित करना और नियंत्रित करना इस कौशल में सम्मिलित है। आज हम जिस सामाजिक प्रतिस्पर्धा में जी रहे हैं उसमें अनेक प्रकार की बाधाएँ आना, विभिन्न क्षेत्रों में असफलता मिलना और इन असफलताओं के कारण कुण्ठा होना स्वाभाविक है। यह बाधाएँ, असफलताएँ और कुण्ठाएँ हमारे जीवन में कभी कम तो कभी अधिक मात्रा में तनाव पैदा करती हैं। तनाव की अनुकूलतम मात्रा हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक भी है और लाभदायी होती है किंतु जब उसकी मात्रा व्यक्ति की सहनशीलता से अधिक हो जाती है तो उसमें तरह-तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होने लगती हैं। आज अधिकतर शारीरिक रोग भी इन तनावों के कारण हो रहे हैं। आज चिकित्सा क्षेत्र में तनाव को विभिन्न बीमारियों का एक प्रमुख कारक माना जा रहा है। इसके निवारण और प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। भगवान् शिवशम्भु को तनाव प्रबन्धन का सबसे बड़ा गुरु कहा जाता है। उनकी भावभक्ति पूर्वक पूजा-अर्चना और ध्यान आज के तनाव को दूर करने में कारगर हैं। □



## अमृतकाल की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उन्नत भारत



**डॉ. अंजनी कुमार झा**  
विभागाध्यक्ष,  
मोडिया अध्ययन विभाग, महात्मा  
गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय,  
मोतिहारी (बिहार)

**अ**मृत काल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के जरिये विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों को समझने के साथ एक राष्ट्रीय सोच विकसित करने में मदद मिल रही है। मूल्य परक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने से सांस्कृतिक कैनवास बदरंग नहीं हो रहा है। आत्मबल के मजबूत होने से बाधाएँ कम आ रही हैं। उसी प्रकार विविध विषयों के समावेश से बहुविषयक पाठ्यक्रमों की तरफ ध्यान जा रहा है, जिससे भारतीय ज्ञान परम्परा

को समझा और गुना जा रहा है। उन्नत भारत की राह पर चलने से छात्रों का शैक्षिक और पेशेवर विकास हो रहा है। समान शिक्षा की सुनिश्चितता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन को बढ़ावा देने और न्यूनतम समान मानकों के अनुसार इसे आगे बढ़ाते रहने का लक्ष्य रखा गया है। मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत शिक्षा के लिए कई तकनीकों के अलावा कोर्स करने और इसमें निरंतरता कायम रखने की भी भरसक कोशिश की गई है। इंडिया की जगह भारत की झलक चारों तरफ मिल रही है। तकनीकी विकास के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हुई है। लर्न टू रीड पर ज्यादा फोकस के कारण स्व उद्यम, स्वावलंबन की तरफ हम ज्यादा

बढ़ रहे हैं। यह समतामूलक, समावेशी, लचीला बहु-विषयक बनाने की संकल्पना को साकार करती है। प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर बल देने से ब्रेन ड्रेन कम होने के साथ-साथ विदेशी छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। यह डिजिटल बुनियादी ढाँचे के उचित समर्थन और वर्तमान डिजिटल अन्तर को पाटने के साथ ऑनलाइन सीखने पर जोर देती है। यह अधिक जीवंत और सामाजिक रूप से जुड़े सहकारी समुदायों के साथ सामंजस्यपूर्ण, सुसंस्कृत, अभिनव और समृद्धि प्रदान कर रही है। यद्यपि शिक्षा के सरोकार बड़े विविधतापूर्ण और जटिल हैं। यह अब केवल डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाने तक सीमित नहीं है। संत गुरुनानक देव



जी ने ठीक ही कहा-विद्या चिंगारी तां परोपकारी यानी विद्या व्यक्ति को विचारवान और विवेकशील बनाती है, ताकि वह परोपकारी और सामाजिक भावना से युक्त होकर एक अच्छे मनुष्य के रूप में जीवन जी सके। शिक्षा के साथ उदात्त भाव जुड़ने से अमृत काल सही में परिणामकारी साबित हो रहा है। मातृभाषा आधारित शिक्षा के कारण खण्डित सोच, दकियानूसी बंद-सी हो गयी है। भाषायी प्रवाह से अंग्रेजी पर निर्भरता कम हो गई। मानव पर्यावरण केंद्रित शिक्षा नीति के सर्वसमावेशी होने के सुपरिणाम आने शुरू हो गए हैं। वैश्विक शिक्षा तंत्र के साथ प्रतिस्पर्द्धा की भला अब क्या जरूरत है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाँच स्तंभों- एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबल, एकाउंटेबिलिटी की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफार्म का भरपूर इस्तेमाल कर नौकरी, सेवा के साथ ऑनलाइन क्लास की तरफ रुझान बढ़ रहा है। असफलताओं से मुकाबला करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी के सबक से सीखें जो नई शिक्षा नीति में विस्तार से है।

स्कूल सच्चे अर्थ में संस्कृति का मंदिर केवल तभी बन सकते हैं, जबकि उसमें चार देवता प्रतिष्ठित हों- मातृभूमि, मनुष्य, पुस्तक और मातृभाषा। प्रेक्षण करना, सोचना, चिंतन-मनन करना, श्रम से खुशी पाना और अपने कार्य पर गर्व करना। उपरोक्त बातों पर हमारी शिक्षा नीति चल रही है। आज प्रतियोगी परीक्षाएँ भी भारतीय भाषाओं में शुरू हो गई हैं। ऐसे में केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई और परीक्षा देने की बाध्यता के खत्म होने से कई जटिलताएँ स्वतः खत्म हो गईं। अंग्रेजी शिक्षा का सबसे घातक प्रभाव यह हुआ कि वह हमें आत्म-विस्मृति की ओर ले गई।

वस्तुतः यह मानव जीवन के विकास के लिए रोजाना की खुराक है, इसलिए भूख के साथ स्वाद भी बदलते रहना चाहिए। Pifs के डाटा के अनुसार सामाजिक और आर्थिक विभेद शैक्षिक असमानता को बनाए रखता है। इस पर अमृत कालीन

शिक्षा व्यवस्था ने खासा ध्यान रखा है। यह एक मजबूत सामाजिक भूमिका और संविधानिक मूल्यों के साथ डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया के सपनों को साकार करने में जुटी है। थोक एक्टिविटी और टेलर टीचिंग भी प्रासंगिक है। शिक्षकों को उनके साथ ऐसे जुड़ना चाहिए ताकि छात्रों को उनके सभी जवाब मिल सकें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं- शिक्षक का कार्य मनुष्य के अंदर छिपी पूर्णता को उजागर करना होता है तथा शिक्षा मनुष्य का निर्माण करती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए स्वतंत्रता दी गई है। अध्ययन प्रक्रिया अधिक सहज हो और शिक्षक की भूमिका facilitator की हो। डॉ. राधाकृष्णन के मत में, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को अध्यात्म के उत्कर्ष की ओर बढ़ाना चाहिए और विज्ञान का परीक्षण और प्रयोग भी इसी दृष्टि से करनी चाहिए। मूल्य शिक्षा पर इसी कारण विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रसिद्ध शिक्षाविद vasili sukhomlinski ने अपने ग्रंथ बाल हृदय की गहराइयों के Flap पर लिखा है - स्कूल सच्चे अर्थ में संस्कृति का मंदिर केवल तभी बन सकते हैं, जबकि उसमें चार देवता प्रतिष्ठित हों- मातृभूमि, मनुष्य, पुस्तक और मातृभाषा। प्रेक्षण करना, सोचना, चिंतन-मनन करना, श्रम से खुशी पाना और अपने कार्य पर गर्व करना। उपर्युक्त बातों पर हमारी शिक्षा नीति चल रही है। आज प्रतियोगी परीक्षाएँ भी भारतीय भाषाओं में शुरू हो गई हैं। ऐसे में केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई और परीक्षा देने की बाध्यता के खत्म होने से कई जटिलताएँ स्वतः खत्म हो गईं। अंग्रेजी शिक्षा का सबसे घातक प्रभाव यह हुआ कि वह हमें आत्म-विस्मृति की ओर ले गई। □





## अमृतकाल और शिक्षा



**डॉ. सतेंद्र कुमार शुक्ल**

सहायक आचार्य,  
हिंदी विभाग,  
रामजस महाविद्यालय,  
दिल्ली विश्वविद्यालय

**भा**रत अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद दुनिया के अनेक बुद्धिजीवियों के द्वारा जिस राष्ट्र के खंडित हो जाने की भविष्यवाणी की जा रही थी, जिसके लोकतंत्र के नष्ट हो जाने का दुष्प्रचार किया जा रहा था, वह राष्ट्र पिछले 75 वर्षों से गजराज की भाँति इस वैश्विक कानून में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। एक अल्प विकसित राष्ट्र से लेकर एक विकासशील राष्ट्र बनने तक की यात्रा भारतीयों की जिजीविषा और उनके मेहनत का परिणाम है।

आने वाले लगभग 25 वर्षों में भारत अपनी स्वतंत्रता का 100 वाँ वर्ष मनाएगा। भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। एक विकसित राष्ट्र सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक रूप से सशक्त होना चाहिए। वैसे तो इनमें से प्रत्येक स्तंभ अपने आप में महत्वपूर्ण है परंतु फिर भी मेरी दृष्टि में शिक्षा इन सब में कहीं अधिक है। क्योंकि वह शैक्षणिक पृष्ठभूमि ही है जो किसी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास की नींव तैयार करती है। इसलिए अमृत काल की समाप्ति तक हमें शैक्षणिक रूप से एक ऐसा समाज तैयार करना है, जो हमें न सिर्फ एक विकसित भारत का निर्माण कर के दे, बल्कि हमें वापस पूरी दुनिया में उसी स्थान पर पहुँचाए, जिस

स्थान पर भारत कभी हुआ करता था।

अमृतकाल में जो स्थितियाँ हैं, उसको देखते हुए हमें शिक्षा को संकुचित दायरे से निकालकर इसे वैश्विक और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। एक तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण मनुष्य की जगह मशीनें और रोबोट कार्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तपन और बढ़ते प्रदूषण के कारण जल, भोजन तथा ऊर्जा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए नए रास्तों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसलिए यह वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उपर्युक्त सभी मुद्दों को हल करने की दिशा में कार्य करें।

भारत के पास एक विशाल ज्ञान परंपरा है। हमारे ऋषि-मनीषी अपनी तपस्या से

हमारे समक्ष एक ऐसी शैक्षणिक विरासत छोड़ गए हैं, जिसका सदुपयोग करना हमारा नैतिक दायित्व है। इसलिए हमें अमृतकाल रूपी वटवृक्ष के तले यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत की वर्तमान शैक्षणिक प्रणाली उसकी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से भी उन तत्त्वों को ग्रहण करें जो मानव के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। हमें इस पर ध्यान देना होगा कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश शैक्षणिक प्रणाली में किस प्रकार से करें कि हमारे बच्चों का उद्देश्य सिर्फ नौकरी के माध्यम से धनार्जन ही ना हो अपितु उनका उद्देश्य एक सशक्त समाज व राष्ट्र का निर्माण करना हो।

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक आधारभूत स्तम्भ के समान होती है। एक उचित शैक्षणिक वातावरण के बिना संभवतः कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए बदलती वैश्विक परिस्थितियों में समय के साथ-साथ शिक्षा में सकारात्मक बदलाव बेहद आवश्यक हो जाते हैं। यदि हम भारत की शिक्षा प्रणाली का आकलन करें तो हम पाएंगे कि 1986 के बाद से देश में शिक्षा में कोई आमूल बदलाव नहीं हुआ। इसलिए समय की आवश्यकता को महसूस करते हुए देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया।

स्वतंत्र भारत में संभवतः यह पहली नीति है, जो देश के लगभग सभी गाँवों, कस्बों, ब्लाकों, जनपदों, बड़ी संख्या में शिक्षकों, शिक्षाविदों तथा शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं अन्य नागरिकों के सुझावों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। पूरे राष्ट्र की भागीदारी के कारण यह सही मायनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है।

नई शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार ने हमारी वर्तमान शैक्षणिक प्रणाली को हमारी प्राचीन ऐतिहासिक शैक्षणिक प्रणाली से जोड़कर देखने का एक नया

नजरिया राष्ट्र के सामने रखा है। इस अमृत काल में जब हमारा देश ऊर्जा से ओतप्रोत है, हमें अपनी शिक्षा नीति की अलख को गाँव-गाँव, कस्बों-कस्बों तक पहुँचाना होगा, क्योंकि तभी समाज का हर व्यक्ति इससे जुड़ पाएगा।

जाहिर सी बात है, इसके लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार अपनी तरफ से तो यथासंभव संसाधन उपलब्ध कराती ही है, लेकिन हमें सरकारी प्रयासों से इतर जाते हुए भी स्वयं के स्तर पर भी प्रयास करना होगा। इसके लिए समूचे शिक्षा जगत को एक टीम की तरह कार्य करना पड़ेगा। यदि कोई एक शैक्षणिक संस्थान किसी नवाचार को अपनाता है, तो sharing is caring के सिद्धांत के अनुसार उसे यह भी प्रयास करना होगा कि उस नवाचार से दूसरे शिक्षण संस्थान भी लाभान्वित हों। हमारे इस तरह के प्रयास सरकार पर हमारी निर्भरता को तो कम करेंगे ही, इसके साथ ही वो स्वयं हमारी दक्षता में भी वृद्धि करेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस मामले में एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरकर सामने

आई है। कला, विज्ञान, वैचारिक शिक्षा, रचनात्मकता, नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य, बहुभाषावाद तथा जीवन कौशल जैसे अनेक आयामों को नीति के माध्यम से साधने का कार्य किया गया है, जो निश्चित रूप से भविष्य की समस्याओं के समाधान का भी मार्ग प्रशस्त करेंगी।

किन्तु अमृत काल में भारत की शैक्षणिक भूमिका को सिर्फ नई शिक्षा नीति परिभाषित नहीं कर सकती बल्कि इसके इधर भी सरकार को अपने स्तर पर वह प्रयास करने होंगे जो शिक्षा नीति में शामिल नहीं किए जा सकते। इसका एक उदाहरण यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा प्रणाली पर जोर दिया गया है किंतु हम सबको पता है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में सिर्फ तीन भाषाएँ ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ तो “कोस-कोस पर बानी बदले चार कोस पर बानी” वाली परंपरा है। इसलिए सरकार और समाज की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह भारत की भाषाओं, विशेष कर प्राचीन भाषाओं का संरक्षण करें। हमें भारत की भाषाई आत्मा का संरक्षण करना होगा।







भारत की भाषाई आत्मा के संरक्षण से आशय यह है कि हमें भारतीय भाषाओं की शब्दावलियों के मानकीकरण (standardization) की ओर भी पर्याप्त ध्यान देना होगा। आप सबने आमतौर पर यह देखा होगा कि हमने देशज और विदेशज शब्दों को ग्रहण तो कर लिया है, किंतु उनके अर्थ भारतीय पृष्ठभूमि के अनुसार सटीक नहीं बैठते। जैसे, आप Religion और धर्म के अर्थ को देखिये। दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में religion का अर्थ पूजा-पद्धति से लिया जाता है, जबकि भारत में धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पद्धति नहीं है। भारत में धर्म एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है, पूजा पद्धति तो इसका बस एक अंश मात्र है।

इसी प्रकार आप Nation और राष्ट्र की अवधारणा को भी देख सकते हैं। पूरी दुनिया में nation को जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता के एक समुच्चय के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत में राष्ट्र की अवधारणा इन सैद्धांतिक तथ्यों से कहीं अधिक बढ़कर है। हमारे लिए राष्ट्र सिर्फ भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि

भारत के पास एक विशाल ज्ञान परंपरा है। हमारे ऋषि-मनीषी अपनी तपस्या से हमारे समक्ष एक ऐसी शैक्षणिक विरासत छोड़ गए हैं, जिनका सदुपयोग करना हमारा नैतिक दायित्व है। इसलिए हमें अमृतकाल रूपी वटवृक्ष के तले यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत की वर्तमान शैक्षणिक प्रणाली उसकी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से भी उन तत्त्वों को ग्रहण करें जो मानव के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। हमें इस पर ध्यान देना होगा कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश शैक्षणिक प्रणाली में किस प्रकार से करें कि हमारे बच्चों का उद्देश्य सिर्फ नौकरी के माध्यम से धनार्जन ही ना हो अपितु उनका उद्देश्य एक सशक्त समाज व राष्ट्र का निर्माण करना हो।

हम अपने राष्ट्र को जननी के रूप में देखते हैं।

ऐसे न जाने कितने शब्द हैं, जिन्हें हमने अपनी सुविधा अनुसार अपनी शब्दावली में शामिल तो अवश्य कर लिया किंतु वे शब्द भारतीय पृष्ठभूमि के अनुरूप सटीक नहीं बैठ पाए। इसलिए हमें प्रयास करना होगा कि हम भारतीय शब्दावलियों में से ऐसे शब्द निकालें जो हमारी परिस्थितियों के अनुसार सार्थक हों।

भाषाई संरक्षण से इतर हमें 'शिक्षा में रस' भी लाना होगा। हमें शिक्षा को एक बोझ बनने देने से रोकना होगा। यदा कदा छात्रों की आत्महत्या के प्रसंग यदि अखबारों में हमें पढ़ने को मिलते हैं तो वह भारत की शैक्षणिक व्यवस्था के सफेद पट्ट पर एक कलंक की भांति दिखते हैं। वह शिक्षा ही क्या जो विद्यार्थियों के अंदर उत्साह ना भरे।

Studying, जो कि स्वयं के अंदर झांकने का तथा अपने मस्तिष्क की व्यापकता को बढ़ाने का एक माध्यम है, उसे अनेक उम्मीदों और नियमों के बोझ के द्वारा "Student + dying = Studying." बना दिया गया था। अतः हमें प्रयास करना होगा कि छात्र अध्ययन के दौरान अधिक उत्सुकता से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएँ। शिक्षा सिर्फ गुणवत्तापूर्ण ही नहीं होनी चाहिए बल्कि वह आनंददायी भी होनी चाहिए।

अमृत काल की समाप्ति तक हमें सिर्फ डिग्रियों वाले युवा नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार परक नैतिक युवाओं का निर्माण करना है। आइए हम सब मिलकर अमृतकाल की समाप्ति तक अपने इस वैभवशाली राष्ट्र को वापस से विश्व गुरु बनाने की दिशा में कार्य करें। □



## अमृतकाल : भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी



**प्रो. मनीषा शर्मा**

संकायाध्यक्ष-पत्रकारिता व जनसंचार एवं व्यावसायिक शिक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विवि. अमरकंटक

**भारत** वर्ष अपनी सनातन संस्कृति, मूल्यों एवं परंपराओं के कारण संपूर्ण विश्व में अलग पहचान रखता है। भारत की सनातन विरासत व कला ने सदैव विश्व को प्रभावित किया है। भारत अतीत में एक बड़ी वैश्विक शक्ति रहा है। उसकी इस शक्ति का प्रभाव भू-राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों ही क्षेत्र में देखने को मिलता रहा है। अनेक विदेशी आक्रमणों के बावजूद भारत भूमि की आध्यात्मिकता और आस्था की प्राण शक्ति ने इस सनातन संस्कृति को जीवंत रखा। भारत ने सदैव अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा व ज्ञान के बल

पर संपूर्ण दुनिया को मार्गदर्शित किया। वर्तमान में जिस वैश्वीकरण को 20वीं सदी का विचार माना जाता है यह वैश्वीकरण का मूल 'वसुधैव कुटुंबकम्' के रूप में भारत की सनातन संस्कृति ने 4000 वर्षों पूर्व विश्व को प्रदान किया था। वर्तमान में केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी के कुशल नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन संस्कृति के व्यापक

प्रचार-प्रसार हेतु संकल्पित है। आज भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर को, परंपराओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित कर रहा है और संपूर्ण दुनिया इसे सराह रही है।

सन् 2014 से भारत ने सांस्कृतिक उत्थान के एक नवीन युग में प्रवेश किया। 500 वर्षों से विवाद में रहे श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और 22 जनवरी 2024 के शुभ दिन प्रभु श्री राम



अमृतकाल में भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत पुरातन व नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए वैश्विक फलक पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। अपने इस सांस्कृतिक अभ्युदय के बल पर भारत 'जगद्गुरु' बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता भारत गौरवशाली इतिहास के साथ वर्तमान में नए आयाम जोड़कर स्वर्णिम भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर है।

जन्मभूमि अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का उद्घोष बनी।

सन 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस की संकल्पना को भारी ध्वनि मत से समर्थन मिला और 21 जून 2015 को जिस प्रभाव से संपूर्ण विश्व में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया वह असली मायने में भारत की इसी सांस्कृतिक धरोहर का, इसी सांस्कृतिक अभ्युदय का जय घोष था। इससे भारत की संस्कृति की महान विरासत योग के रूप में वैश्विक सम्मान से सम्मानित हुई।

चार धाम में से एक केदारनाथ धाम का कायाकल्प हो चुका है। इसी के साथ कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद मंदिरों के पुनरुद्धार का कार्य प्रारंभ हो चुका है। माता हिंगलाज, रघुनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है। उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर, काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर आज विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। रामायण सर्किट रूट को विकसित किया जा रहा है। काशी, उज्जैन, अयोध्या धार्मिक-आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो रहे हैं और देश की



अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले के चालुक्य शासन में बने मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी नवजीवन मिल चुका है।

आज भारत के बाद अमेरिका में सर्वाधिक हिंदू मंदिर हैं। इसी साल फरवरी में बसंत पंचमी के दिन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था हिंदू मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी के कर कमलों से संपन्न हुआ। यह मंदिर भारत



की उस बढ़ती वैश्विक ताकत को दिखा रहा है जिसे वैश्विक परिदृश्य में सम्मान दिया जा रहा है। यह यूएई का पहला गैर इस्लामिक पूजा स्थल है। यह वैश्विक परिदृश्य में हमारे सांस्कृतिक अभ्युदय को दर्शाता है। जी-20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी संस्कृति, विविधता सभ्यता के बल पर वैश्विक क्षेत्र में फिर से नव ऊर्जा, नवजीवन के साथ आगे बढ़ रहा है।

जब भी किसी देश की आर्थिक शक्ति के साथ उसकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत को स्वीकृत किया जाता है; तब सही अर्थों में वैश्विक पटल पर उसे सम्मान मिलता है। ऐसे में आज भारत अपने विकास व विरासत की साझा सोच के साथ भारतीय संस्कृति को नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में पहुँचा रहा है। अमृतकाल में भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत पुरातन व नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए वैश्विक फलक पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। अपने इस सांस्कृतिक अभ्युदय के बल पर भारत 'जगद्गुरु' बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता भारत गौरवशाली इतिहास के साथ वर्तमान में नए आयाम जोड़कर स्वर्णिम भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। □





## अमृत काल के भारत में

### पं. दीनदयाल उपाध्याय के रोजगार विषयक विचारों की प्रासंगिकता



**डॉ. धीरज कुमार पारीक**

सह आचार्य, अर्थशास्त्र  
सनातन धर्म राजकीय  
महाविद्यालय, ब्यावर (राज.)

**भारत** के अमृत काल में रोजगार की रणनीति पर विचार करने से पूर्व हमें इतिहास में भारत में रोजगार की स्थिति का पुनरलोकन करना आवश्यक है। विदेशी आक्रांताओं (मुगलों एवं अंग्रेजों) से पूर्व का भारत आत्मनिर्भर ग्रामों का भारत था। भारत में तत्समय लघु एवं मझोले उद्योग, रोजगार के प्रमुख साधन होते थे। जिनका आधार कृषि एवं पशुपालन था। तत्कालीन भारत, विश्व का ऐसा राष्ट्र था जो पूर्णरोजगार (full employment) की कल्पना को वास्तविकता के धरातल पर साकार करता था।

विदेशी आक्रमणकारियों, चाहे वह मुगल हो या अंग्रेज, उन्होंने भारतीय अर्थतंत्र की रोजगारमूलक प्रणाली को कमजोर एवं छिन्न भिन्न किया। स्वतंत्रता के पश्चात भी विदेशों (पहले रूस फिर अमेरिका) का मुँह ताकती, नेहरू व इंदिरा की आर्थिक नीति, भारत में रोजगार का आत्मस्फूर्त (self generated) स्रोत विकसित करने में असफल रही।

यद्यपि स्वतंत्रता के प्रारंभिक काल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के लिए आत्मकेंद्रित आर्थिक नीति एवं रोजगार नीति की विशद व्याख्या की थी, किंतु राजनीतिक सौतेलेपन के कारण उसे समुचित महत्त्व प्रदान नहीं किया गया था। आज भारत अमृतकाल के इस दौर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भारतीयता से युक्त रोजगारपरक विचारों का उपयोग करके अपनी आत्मस्फूर्त रोजगार रणनीति बना

सकता है।

#### पं. दीनदयाल उपाध्याय के रोजगार विषयक विचार -

दीनदयाल उपाध्याय भारत में व्याप्त बेकारी की समस्या से चिंतित थे और इसका कारण हमारी समकालीन आर्थिक व्यवस्था में छिपा हुआ मानते थे। उन्होंने सबको काम (work for all) को भारतीय अर्थ नीति का मूलाधार स्वीकार किया था। उपाध्याय (1956) ने 'बेकारी की समस्या और उसका हल' विषयक पुस्तक में बेरोजगारी पर अपने आर्थिक विचारों को प्रस्तुत किया।

भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रंथों, उपनिषदों में भी यही कामना करते हैं कि 'काम करते हुए हम सो वर्ष जीवित रहे।' **कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत् समाः।** (उपनिषद)

इसी प्रकार कर्म की प्रधानता को



भगवत गीता में श्रीकृष्ण भी स्वीकार करते हैं और भारत भूमि को कर्मभूमि कहते हैं। अतः हमारी संस्कृति एवं परंपरा के अनुरूप भारतीय अर्थ नीति का आधार सबको काम ही हो सकता है। बेरोजगारी अभागी है, यह भारत की स्वभाविक प्रकृति नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय सबको काम मिले इसे भारतीय शासन का कर्तव्य मानते हैं।

**बेरोजगारी के कारण** - उपाध्याय (1956) के अनुसार 'कार्य की प्रकृति की आवश्यकता के अनुरूप योग्य व्यक्तियों की कमी और जनाधिक्य, बेरोजगारी के स्थाई कारण हैं। यह दोनों ही कारण भारत में विद्यमान हैं।' उपाध्याय इस बेरोजगारी के समाधान के लिए शिक्षा की पद्धति और उद्योग धंधों के विकास की संशोधित रणनीति में सुधार का सुझाव देते हैं।

भारतीय अर्थ नीति का आधार पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की नकल ना होकर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए।

भारतीय समृद्धि एवं रोजगार वृद्धि का आधार हमारे कुटीर एवं ग्रामोद्योग ही हो सकते हैं।

हमारी आर्थिक नीति का केंद्र औद्योगीकरण या कोई अन्य भौतिक लक्ष्य ना होकर मनुष्य ही होना चाहिए। मनुष्य को काम मिले और वह सुखी रहे यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए।

श्रम और मशीन में एक समन्वय होना

चाहिए जैसे-जैसे उद्योगों की अवस्था में उन्नति होती जाती है, उनका बाजार मिलता जाता है, मनुष्य स्वयं मशीनों का सहारा लेता है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक होनी आवश्यक है।

भारत में कुटीर और ग्रामोद्योग वृहद पैमाने पर रोजगार देने में सक्षम है। जिन क्षेत्रों में बड़े उद्योग इन लघु उद्योगों के हित में चले वहाँ अवश्य चलाने चाहिए।

**औद्योगिकीकरण कैसे हो?**

भारत की द्वितीय औद्योगिक नीति एवं पंचवर्षीय योजना में भारी एवं सार्वजनिक

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। वे एक वर्ष की औद्योगिक शिक्षा अनिवार्य करने का भी सुझाव देते हैं। एक रोजगार से छंटनी के उपरांत दूसरे काम की तलाश करते हुए, अनैच्छिक बेरोजगार के लिए यूरोपीय देशों के समान 'बेकारी बीमा योजना' प्रारंभ करने का सुझाव देते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जितनी भी योजनाएँ हैं, उन्हें जनशक्ति का अधिकतम उपयोग करना चाहिए।

औद्योगीकरण के जिस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया, उपाध्याय उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे।

उपाध्याय कुटीर एवं ग्रामोद्योग को आधार बनाकर बड़े उद्योगों को उनके साथ समन्वित करने के पक्षधर थे। इसके साथ ही दीनदयाल उपाध्याय (अगस्त 1953) के विचार से अनुसंधान केंद्रों की स्थापना, स्वदेशी को प्रोत्साहन, उद्योग शिक्षा केंद्रों की स्थापना, कुटीर उद्योगों को बिक्रीकर से राहत आदि औद्योगीकरण की नीति के मुख्य आयाम होने चाहिए।

**औद्योगिक शिक्षा** - उपाध्याय के अनुसार पृथक औद्योगिक शिक्षा केंद्रों के अतिरिक्त साधारण (माध्यमिक) शिक्षा में भी औद्योगिक शिक्षा को जोड़ना चाहिए। "माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने तक नवयुवक को अपना धंधा भी आ जाना चाहिए। टेक्निकल और वोकेशनल शिक्षा केंद्रों में भी शिक्षा प्राप्त नवयुवक इस योग्य नहीं बन पाते हैं कि वे स्वयं कोई कारोबार शुरू कर सकें।" इस प्रकार उपाध्याय का विचार है कि भारत के नवयुवक केवल सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी पर ही निर्भर ना हों बल्कि स्वयं व्यवसायी (Self Employed) बनने की योग्यता भी अर्जित करें। इस संबंध में दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी (1937) की बेसिक शिक्षा एवं रोजगार विषयक विचारों से बहुत अधिक समानता रखते हैं।

**बेकारी की समस्या का मूल** - उपाध्याय (अगस्त 1953) के अनुसार तीन कारकों का पारस्परिक संतुलन बिगड़ने से अर्थ संबंधी समस्याएँ पैदा होती हैं। यह तीन तत्व इस प्रकार हैं -

1. जनसंख्या,
2. जनसंख्या की आवश्यकताएँ,
3. उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन एवं व्यवस्था।

हमारे देश की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है, किंतु उसके अनुपात में उत्पादन के साधन एवं उत्पादन नहीं बढ़

पाया है। इसी का परिणाम है कि हमारी आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं हो रही हैं जिस कारण हमारा जीवन स्तर बहुत नीचा है।

उपाध्याय के अनुसार हम उत्पादन के साधनों की वृद्धि के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करें और उत्पादन इस ढंग से हो कि हम देश के सभी लोगों को काम दे सकें। ऐसा नहीं होने पर उत्पादक साधनों का स्वामी, एक छोटा सा वर्ग रह जाएगा। जिसके फलस्वरूप उत्पादित वस्तुओं का समान रूप से वितरण नहीं होगा। उपाध्याय (1956) के शब्दों में “अब बेकारी प्रमुखतया यांत्रिक है। यंत्र मनुष्य की जगह लेता जा रहा है तथा मनुष्य बेकार होता जा रहा है। हमें इस संबंध में समन्वयात्मक दृष्टि से काम करना होगा।” दीनदयाल उपाध्याय यंत्रीकरण के विरुद्ध नहीं हैं किंतु वे अर्थव्यवस्था के विकास की अवस्था के आधार पर स्वाभाविक यंत्रीकरण को ही सही मानते हैं।

**प्रत्येक को काम का सिद्धांत ( Work for All Model )** - दीनदयाल उपाध्याय (1956) ने मझे हुए अर्थशास्त्री के समान अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो बेरोजगारी, असमानता एवं केंद्रीकरण की समस्याओं का एक साथ समाधान प्रस्तुत करता है।

“प्रत्येक को काम का सिद्धांत यदि स्वीकार कर लिया जाए तो संवितरण की दिशा निश्चित हो जाती है, अधिक केंद्रीकरण के स्थान पर हम विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ते जाते हैं।” उपाध्याय इस सिद्धांत की व्याख्या एक समीकरण के माध्यम से करते हैं-

$$ज \times क \times य =$$

यहाँ

ज = समाज के काम करने योग्य व्यक्ति (जनसंख्या),

क = काम करने की अवस्था एवं व्यवस्था (काम),

य = मशीनीकरण (यंत्र)

= अर्थव्यवस्था की प्रभावी माँग (इच्छा), जिसकी पूर्ति की उसमें शक्ति है इस सूत्र के अनुसार यदि ‘ज’ स्थिर रहे, तो उसके अनुपात में ‘क’ और ‘य’ को बदलना होगा। जैसे-जैसे हमारी अर्थव्यवस्था में माँग बढ़ती जाएगी, हमें ऐसे यंत्रों का उपयोग करना होगा जिनके सहारे हम अधिक उत्पादन कर सकें।

अर्थात् प्रभावी माँग के बढ़ने से हमारी समस्या हल होगी किंतु इसका संबंध हमारी क्रय शक्ति से है। अतः सरकार को क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करना होगा। विदेशी निर्यात बढ़ाकर भी इसे बढ़ाया जा सकता है। उपाध्याय इसके लिए सरकार की आयात निर्यात नीति को सुधारने का सुझाव देते हैं। दूसरे शब्दों में वे निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात के स्थान पर स्वदेशी प्रोत्साहन की बात करते हैं।

यंत्रीकरण पर उपाध्याय के विचारों को गहराई से समझना आवश्यक है। उपाध्याय (1958) के अनुसार “आज भारत में दो प्रकार के वर्ग हैं। एक, तो आधुनिक यंत्रीकरण के बिल्कुल विरोधी है। दूसरे वे हैं, जो अनियंत्रित रूप से यंत्रीकरण की वृद्धि चाहते हैं।” दीनदयाल उपाध्याय इन दोनों ही वर्गों को गलत मानते हैं। उनका सिद्धांत है कि जैसे-जैसे देश की क्रयशक्ति एवं प्रभावपूर्ण माँग बढ़ती जाए, हम यंत्रों का अधिकाधिक उपयोग करते जाएँ।” इस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय के यंत्रीकरण के स्वाभाविक विकास से संबंधित विचार उस समय के सभी आर्थिक विचारकों से श्रेष्ठ थे।

**सिद्धांत के निष्कर्ष** - उपाध्याय के सिद्धांत के निष्कर्ष को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि ‘क्रय शक्ति और माँग बढ़ाई जाए, फलस्वरूप यंत्रों की माँग अपने आप बढ़ जाएगी।’ इस प्रकार उपाध्याय मानव एवं मशीन के मध्य सामान्य विरोध को अस्वीकार करते हैं।

**प्रत्येक को काम का सवैधानिक अधिकार हो** - दीनदयाल उपाध्याय अर्थशास्त्र के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते

हैं। दीनदयाल उपाध्याय (सितंबर 1956) 215 के अनुसार “राजनीतिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की ओर तो हम बढ़ रहे हैं, परंतु आर्थिक लोकतंत्र की उपेक्षा कर रहे हैं। दोनों ही पंचवर्षीय योजनाएँ बेकारी की समस्या को निपटा नहीं सकी हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण गलत है। 40 करोड़ जनसंख्या वाले भारत में श्रमबल का प्राचुर्य है। हमें ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है, जिसमें पूंजी की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाए।” इस प्रकार उपाध्याय तकनीक के चयन के मुद्दे पर पूंजी प्रधान तकनीक की अपेक्षा श्रमप्रधान तकनीक को भारत की तत्कालीन आर्थिक अवस्था में अधिक उपयुक्त मानते हैं।

**बेकारी कैसे दूर हो** - दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार बेरोजगारी को दूर करने का दायित्व सरकार का होता है। इसे दूर करने के लिए उपाध्याय (1958) निम्नांकित सुझाव देते हैं -

1. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। वे एक वर्ष की औद्योगिक शिक्षा अनिवार्य करने का भी सुझाव देते हैं।

2. एक रोजगार से छंटनी के उपरांत दूसरे काम की तलाश करते हुए, अनैच्छिक बेरोजगार के लिए यूरोपीय देशों के समान ‘बेकारी बीमा योजना’ प्रारंभ करने का सुझाव देते हैं।

3. पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जितनी भी योजनाएँ हैं, उन्हें जनशक्ति का अधिकतम उपयोग करना चाहिए।

4. ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए सहायता कार्य प्रारंभ करने का सुझाव देते हैं। सड़कें, ईमारतें, बांध, कुएँ और तालाब निर्माण करके गाँव में मौसमी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है।

5. छोटे-छोटे उद्योग केंद्र, सहकारी आधार पर चलाए जाएँ तो स्वदेशी की भावना एवं पारस्परिक संबंधों के सहारे उनके लिए बाजार भी मिल सकता है। □





## अमृतकाल का भारत और आधारभूत विकास



### डॉ. अरविन्द पारीक

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,  
वनस्पति शास्त्र विभाग, महर्षि  
दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय,  
अजमेर (राजस्थान)

**2047** में भारत की स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे होने पर, देश एक नए युग की शुरुआत करेगा। अपने अमृत काल में भारत आधारभूत संरचनात्मक विकास के क्षेत्र में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेगा। अपने इन सौ वर्षों में भारत समावेशी विकास, प्रतिभा और आविष्कार के क्षेत्र में वर्तमान विकसित राष्ट्रों से कहीं अग्रिम पंक्ति में खड़ा नजर आने वाला है। अमृत काल में भारत का संरचनागत विकास का दृष्टिकोण उत्साहवर्धक तथा आशातीत होगा।

अमृत काल में भारत के आधारभूत विकास के विभिन्न पहलुओं पर सक्षिप्त चर्चा करना समीचीन होगा।

### शहरी संरचना

भारत के शहर 2047 तक जीवंत, स्थायी और समावेशी शहरी क्षेत्रों के रूप में विकसित किये जायेंगे। शहरी संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव इस प्रकार किये जायेंगे जो बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं एवं सुख

सुविधाओं को ध्यान में रखने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के धारणक्षम (Sustainable) उपयोग पर आधारित हो।

**1. ऊर्ध्वाधर शहरीकरण (Vertical Urbanization) :** शहरों के अनियंत्रित विस्तार सीमित करने के लिए, शहरीकरण ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, जिसमें उच्च इमारतें और मिक्सड-यूज विकास शामिल होगा। स्मार्ट शहर नियोजन और डिजाइन सिद्धांत के अनुसार, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए स्थान का उपयोग किया जाएगा, साथ ही पैदल चलने की सुविधा को बढ़ावा दिया जाये और हरित स्थानों को बचाया जाये। स्मार्ट शहर इस प्रकार से नियोजित किये जाएँ कि उनके जल, ऊर्जा और लकड़ी जैसी आवश्यकताओं के उत्पादन में शहर आत्मनिर्भर हो। ऊर्ध्वाधर शहरीकरण भूमि को खेती और वन उपयोग के लिए संरक्षित रख सकेगा, साथ ही वर्षा जल के भूमिगत संचयन को भी बढ़ाएगा।

**2. स्मार्ट ग्रिड्स और जल प्रबंधन :** स्मार्ट ग्रिड्स और पानी की प्रबंधन प्रणालियाँ, संसाधनों के अधिकतम और इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देंगी, बर्बादी को कम करेंगी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी।

**3. उचित आवास विकल्प :** विभिन्न

प्रकार के आवास के विकल्प उपलब्ध होंगे, जैसे माइक्रो-अपार्टमेंट्स, को-लिविंग स्थानों और पर्यावरण-अनुकूल हाउसिंग विकास की संभावनाओं को तलाश कर विकसित किया जायेगा। नए और कम लागत वाले आवास समाधानों से भारत की शहरी जनसंख्या की आवास की माँग पूरी होगी।

**4. डिजिटल प्रशासन :** ई-प्रशासन पहल से नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी, सरकारी प्रक्रियाओं में सरलता और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देंगे और नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुँचने, समस्याओं की रिपोर्ट करने और निर्णय लेने में शामिल होने में सक्षम करेंगे।

### परिवहन संरचना

भारत की परिवहन संरचना 2047 तक बहुत विकसित होने वाली है, जिससे उसकी आवश्यकताओं को एक तेजी से आगे बढ़ते समाज के लिए संतुलित किया जा सके। उम्मीद है कि आगे वर्णित उपक्रमों के माध्यम से परिवहन संरचना एक आधुनिक रूप ले सकेगी।

**1. हाइपरलूप नेटवर्क :** प्रौद्योगिकी ने शहरी परिवहन को बदल दिया है, जो यात्रा

समय को कम करता है और प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। हाइपरलूप कॉरिडोर, जैसे मुंबई-दिल्ली और बेंगलोर-चेन्नई कॉरिडोर, एयर टैक्सी आदि दूरी को द्रुत गति और अल्प समय के साथ नए अनुभव और आयाम देंगे।

**2. शून्य उत्सर्जक वाहन :** भारत में शून्य उत्सर्जन वाले वाहन, जैसे इलेक्ट्रिक कार, बसें और दो-पहिया वाहन, काफी लोकप्रिय होने वाले हैं। स्वच्छ यातायात साधनों के विकास को तेजी से बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी प्रोत्साहन, बैटरी प्रौद्योगिकी और चार्जिंग संरचना में सुधार के साथ तेजी से बढ़ाया जाने वाला है।

**3. एकीकृत परिवहन हब :** एकीकृत परिवहन केंद्रों में विभिन्न प्रकार के परिवहन जैसे उच्च गति रेल, मेट्रो, बसें और साइकिलिंग संरचनाएँ हो सकती हैं, जो संयुक्त रूप से एक ही स्थान से संचालित होकर आम जन को सुविधा के साथ साथ व्यक्तिगत साधनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन हेतु प्रोत्साहित करे। इन केंद्रों की स्थापना से न केवल यात्रा को सुरक्षित और द्रुतगामी बनायेंगे, बल्कि इनसे मनोरंजन, आर्थिक और व्यापारिक कार्य भी जुड़ सकेंगे।

**4. हरित स्वच्छ हवाई अड्डे :** भारत के हवाई अड्डे सोलर पावर जनरेशन, बारिश के पानी का संचयन और ऊर्जा की कुशल योजना को समाहित करते हुए विकसित होंगे। ये हरित हवाई अड्डे वर्तमान में प्रदूषण का पर्याय बन चुके हवाई अड्डों के विपरीत हरित उर्जा और वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में स्वाबलंबी हो सकेंगे।

### ऊर्जा संरचना

भारत 2047 तक अपनी ऊर्जा व्यवस्था को नवीनीकृत कर, विविधता और पर्यावरणीय सुरक्षा की ओर ले जाएगा। ऊर्जा संरचना में बदलाव इस प्रकार से होंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के क्षय से उर्जा उत्पादन से हटकर पवन और सौर ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों पर ही निर्भरता रह जाये।

**1. नवीनीकरण प्रणाली :** भारत, सौर और पवन ऊर्जा के मिश्रण के माध्यम से विश्व



**भारत का 2047 तक नवाचार, समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल आधारभूत विकास का दृष्टिकोण ऐसा हो जो, रणनीतिक निवेशों, नीति सुधारों और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के माध्यम से एक श्रेष्ठ संरचना नेटवर्क बनाए, जो आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक प्रगति को संभव बना सके।**

स्तर पर इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बन जाने की क्षमता रखता है। बड़ा रेगिस्तान और उच्च वायु प्रवाह के क्षेत्र इस दिशा में आगे बढ़ने में हमारे लिए वरदान हो सकते हैं। इस क्षेत्र में बड़े निवेश बैटरी प्रौद्योगिकी के विकास के साथ नवीनीकरण परियोजनाएँ सस्ते प्राकृतिक ऊर्जा उत्पादन को सुनिश्चित करेंगी।

**2. ऊर्जा भंडारण क्रांति :** उन्नत बैटरी और हाइड्रोजन ईंधन सेल जैसे ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों में बड़ी सफलता से इनके उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से ग्रिड स्थिरता में सुधार होगा, उद्योगों और परिवहन में विद्युतीकरण की सुविधा बढ़ेगी। हो सकता है 2047 तक भारत में सिर्फ विद्युत वाहनों

से ही परिवहन आवश्यकता पूरी हो सके।

**3. विकेन्द्रीकृत ऊर्जा सिस्टम :** स्थानीय समुदायों को स्वतंत्र रूप से ऊर्जा उत्पादन, संग्रहण और वितरण करने की क्षमता विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों से मिलेगी, जैसे माइक्रोग्रिड्स और समुदाय-आधारित नवीनीकरण परियोजनाएँ। ऐसी परियोजनाएँ ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी।

**4. स्मार्ट ऊर्जा संरचना :** ऊर्जा वितरण और उपयोग तंत्र को सुधारने के लिए स्मार्ट ऊर्जा ग्रिड्स का निर्माण ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, स्मार्ट मीटर और IoT-सक्षम सेंसर का समीचीन उपयोग संभव होगा। ऊर्जा के किफायती मापदंडों का प्रोत्साहन और स्मार्ट उपकरणों और घर के आटोमेशन प्रणालियों के उपयोग का मांग और उत्पादन के अनुसार प्रबंधन हो सकेगा।

कुल मिलाकर, भारत का 2047 तक नवाचार, समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल आधारभूत विकास का दृष्टिकोण ऐसा हो जो, रणनीतिक निवेशों, नीति सुधारों और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के माध्यम से एक श्रेष्ठ संरचना नेटवर्क बनाए, जो आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक प्रगति को संभव बना सके।

जब भारत अपने स्वतंत्रता के सौ वर्षों की यात्रा पर निकटस्थ होगा, एक मजबूत infrastructure की नींव समाज की समृद्धि, समानता और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने में एक केंद्रबिंदु का काम करेगी। □



## Bharath and its Brief History on Peace and Social Harmony



**Dr. G.V. Snigdha Raj**

Assistant Professor,  
Centre for Comparative  
Religion and Civilizations,  
Central University of Jammu.

**B**harath is a country with many cultures, religions, traditions, customs, communities, languages, etc. It is known to be called a country with unity despite many diversities. It is the second most populated country in the world. Even with such a huge population, the country is known to maintain its peace and harmony. Harmony helps in the socio-economic prosperity of a country. It should also be noted that maintaining complete social harmony is a myth. For example, we generally see disturbances between two brothers who belong to the same family and it is quite natural for the head of the family to try and sort the conflict. It may be because of

differences in their way of thinking and understanding things. If this can occur between the siblings of the same family it can also be seen in a society with many variations. It is the responsibility of the governing body to resolve such conflicts occurring in society for the maintenance of peace and harmony. A country can progress once it achieves that harmony.

Social harmony indeed can be understood with a simple term as a 'perfect society'. It is that society that has fairness in justice, the applicability of law, implementation of rights, and living harmoniously with each other. A peaceful society lets people's minds think freely therefore leads to an advanced society.

### **History of Social Harmony**

Bharath, the birthplace of the Vedas, the Bhagawath Geeta, Yoga, Gautama Buddha, Vardhaman Mahavir, etc has always attracted people from all

over the world. During the Saraswati Sindu Civilization, there was no evidence of violence among the people. There are terracotta figurines that provide proof of people practicing yoga then which promotes non-violence, and harmony. Later in Vedic times, the Vedas had immense knowledge and the people who lived in that period experienced an egalitarian and peaceful society. Ancient universities like Taxila, Nalanda, Vikramashila, etc are known to accommodate thousands of students who belong to different ethnicities and regions. The accomplishments Bharath has seen are huge in number at that point in time. The ancient rulers some of whom came from outside Bharath indeed adopted the culture and way of life of this country and successfully maintained the harmony of the country. This resulted in the flourishing of



intelligence and skills among people thus leading to the emergence of various schools of art and architecture. The metallurgy of the ancient Bharath was so advanced that even the present scientists who use advanced machinery are unable to decipher the formula behind it. The Muslim invasion did disturb the harmony to an extent but the local warriors tried their best to defend their land and people.

In modern times the British ruled our country for a long time and they have successfully destroyed peace and harmony by injecting the idea of communal difference and forcefully converting people. They even introduced separate elections based on religion. This idea was so deeply rooted in the minds of the people that it indeed destroyed the peace of the country. The Britishers did it with the motive of divide and rule so that they could plunder the treasures of the country. India which was called the 'Sone ki Chidiya'(Golden Sparrow) for its wealth and prosperity was destroyed by the Britisher policies. The result was an impoverished country.

Even though the Britishers used many tactics to break India based on religion, community, race, etc many reformers like Swami Dayananda Saraswati, Ishwar Chandra Vidhya Sagar, Swami Vivekananda, etc tried to motivate the youth and preserved the integrity of the country. Thousands of freedom fighters laid down their bodies in the struggle for independence. Even after independence Bharath still had many regions which couldn't be part of it. It was Sardar Vallabhai Patel who was successful in integrating 562

princely states. He had to take extra measures by initiating Operation Polo and saved Hyderabad from joining with Pakistan.

Being ruled by the Britishers for more than 200 years impacted the minds of the people as a result they are still divided on the lines of religion and community. The constitution of India was drafted to reduce these differences. The political parties then took advantage of the differences present between people and further separated them. As a result, there occurred many clashes and resulted in the death of many innocents. The present government seriously worked on these issues and sorted them one after the other. The best example is Jammu and Kashmir. Even though it is called the paradise of the world the real picture was entirely different. The youth were provoked by the extremist forces

**The dream of VIKSIT BHARATH 2047 can only be possible through peace and social harmony between people. The present government is working towards it. As part of decentralization, the present government has asked every individual to contribute their part in making it a reality, especially the youth. Bharath is a country with a very long history many tried to invade it, and even plundered its treasures but the harmony among the people is still intact and there are disturbances but it should be noted that nothing can be perfect.**

as a result there was no peace in the valley. After the removal of Article 370, the scenario is completely transformed. The youth of Jammu and Kashmir are now involving themselves in educational activities and are trying to pursue better careers. Once a disturbed area is now famous for its tourist spots. Outsiders who when having a general conversation would talk about the disturbances present in the valley are now planning to visit it and spend quality time with their family.

In the end, Bharath never invaded any other country and always believed in the principle of Vasudaiva Kutumbakam (the whole world is one family). It played an active role and helped other countries fight Coronavirus by distributing its vaccines for free. Bharath has always given a helping hand to other countries during calamities irrespective of its relations with other countries and there is no wrong in saying that it's a Vishwaguru. It always maintained social harmony with other countries. The age-old cultural values of Bharath have always taught peace and harmony.

The dream of VIKSIT BHARATH 2047 can only be possible through peace and social harmony between people. The present government is working towards it. As part of decentralization, the present government has asked every individual to contribute their part in making it a reality, especially the youth. Bharath is a country with a very long history many tried to invade it, and even plundered its treasures but the harmony among the people is still intact and there are disturbances but it should be noted that nothing can be perfect. □



to make the strong developed nation. Poverty and unemployment in the country can be eliminated totally when infrastructure development takes place in balanced way across the country. Infrastructure development automatically creates the employment opportunities to all the sections of people in various forms and then leads to elimination of poverty.

After the infrastructure development needs to be focused on the strengthening of industrial setups, food processing units for not only satisfying the domestic needs but also for exporting the other countries. Still, we are not self-sufficient in the production of essential commodities, toys, garments and other accessories etc. For example, in the production of garments we are far behind Bangladesh. One main driver of Bangladesh's economic growth is the apparel and textile industry. Bangladesh's primary source of foreign exchange gains comes from exporting clothing and textiles. Now Bangladesh has reached the second largest exporter of ready-made garments products while India is one of the major exporters of raw materials and importers of garments from Bangladesh. To speed up production of these sectors needs to be utilized the talent of our country youth rather than sending them to the other countries. In our country handloom and power loom sector are biggest employment generating sectors which need to be promoted for producing the garments and textile products not only for domestic purpose and also for export into the international markets.

Another important one is brain drain. It is not new one but it is thinkable subject. According to the report of the MHFW technical

**Next 25 years India needs to be under the strong leadership and government as we have right now. Under the visionary leadership only country can become Vikasit Bharat by 2047. If we look into the world, All the developed and even some of the developing countries either have two-party or single party system. They have clear cut agenda that is national interest. Country like India we have multiparty system across the country. Each party has its own agenda rather than national interests.**

group on population projections, Youth between the ages of 15 and 29 make up 27.2% of the population in 2021; by 2036, that percentage is expected to drop to 22.7, but 345 million people is still a huge number. As the world's largest populous country, our country has a demographic dividend as compared to any other country. Since independence, our country had its own disadvantage in utilization of its youth services and talents for growth and development of the country. As a consequence, youth of nation migrated to other countries in search of employment opportunities. The youth of our country became a worthy addition to multinational companies and developed countries at the cost of their own country's growth and development. As per UN International Migration stock report Indian migrants' stock to rest of the world was 17.86 million. As per OECD data, In USA 16058 Indian trained nurses were working in 2020, in United Kingdom 32565

were working, in Australia 14015 were working and in Canada 6828 were working until 2021. Not only this filed, but there are other professional jobs in which lakhs of Indians are working. Country could have benefited in the form of foreign exchange reserves if most of the professionals earning had been sent to home country. Only people who are working in non-professional works whose earnings are coming to the home country. Professionals who went to in search of high earnings and dollars have been benefited through Government educational services. Destination countries are not ready to lose services of Indian professional's, in reward to this they are providing permanent citizenship to Indian professionals in their own countries. It is a simple logic whatever you are earning here and spend that money here only. The country needs to stop the migration of the Indian professionals and need to utilize them for national development. Moreover, it is golden opportunity to our country to utilize the Indian diaspora services to make our country Vikasit Bharat by 2047.

Next 25 years India needs to be under the strong leadership and government as we have right now. Under the visionary leadership only country can become Vikasit Bharat by 2047. If we look into the world, All the developed and even some of the developing countries either have two-party or single party system. They have clear cut agenda that is national interest. Country like India we have multiparty system across the country. Each party has its own agenda rather than national interests. In this background, Dream of Vikasit Bharat can be real if country hold the visionary leader and ambitious people for the development of the nation. □





## Rising Bharat and NEP 2020



**Chandan K. Panda**

Teaches at Rajiv Gandhi University (A Central University), Itanagar.

**E**ducation is the strongest pillar in a democratic country. The meaning, importance and continuity of democracy stand on the strength of education. National Education Policy (NEP) 2020 assumes great significance in this direction. NEP 2020 constitutes the new vision of education in India. The Union Cabinet of India approved it on 29 July 2020. This policy aims to revitalize Bharat's education system. The urgency of this reform was deeply felt because the synthetic layer of political correctness had unsettled the education system since independence. Distancing the

Indians from their cultural roots was the primary strategy of education. History, in this connection, was used as a medium of alienation. Cultural alienation was its objective. Ideologically-stuffed history lost its objectivity. The subjective constructions of history were circulated as the true history of India. History plays a significant role in identity formation.

The strength of a country depends on its past. If the past is not adequately or accurately represented and handed down, the future will not be significant. The identity of a nation is always anchored in the past. Therefore, Sri Aurobindo reiterated the significance of revisiting the past for unity, strength and identity. In his works, he discusses the role of the Indian Renaissance in the 19th

century in uprooting the British from Indian soil. But the post-Independence India had a very different trust with history. History became ideologically determined. A specific ideological framework constructed history with precise objectives in mind. They developed cultural alienation among the Indians. The trajectories of the post-independence reality were utterly antithetical to the civilisational strengths of India. In Pre-Independence India, the Bhagavad Gita was interpreted by Aurobindo, Tilak, Lala Lajpat Rai, Gandhi, Vinoba, and so on. It became the guiding light and inspired the Indians to form unity to present a collective resistance to British rule. The logic of the reinterpretation of the Bhagavad Gita was to address the cultural

imagination of the Indians. This effort presented phenomenal results and united India in the spirit of securing freedom. But the journey in the post-Independence India was completely different.

The morbid obsession for secularism, socialism and political correctness guided the country to question its civilisational foundation. Culture became a casualty. Unfiltered Western theories and ideologies were packed into the Indian educational curriculum, especially in the Humanities and Social Sciences, without assessing the damage that might cause. The perennial wisdom of the Bhagavad Gita was not taught any more. The dialogic traditions of the Upanishads were not found in the curriculum. The Western social theories taught young Indian students to question anything and everything without guiding them on how to be responsible. The importance of being a good citizen who places the nation's priority first was not featured in our education. Rights replaced duties. Patriotism was called politically incorrect. Teaching postmodernism, poststructuralism, new historicism, cultural materialism, etc., made the space of social science overtly political, where Bharat's civilisational past was looked down upon. Unfortunately, this exercise of blatant rejection is also selective. Arun Shourie effectively summarises this tendency in his book *Eminent Historians: Their Technology, Their Line, Their Fraud*.

**The journey of our education since Independence, which carried much of the colonial model and was penetrated by the left ideologies, was not easy. It specialised in uprooting India from its civilisational ground. This cultural deracination project continued for over a few decades. The modern Indian history developed its antithesis after a long spell of lethargy. NEP 2020 may be conceived as an antithesis that aims to reverse the unreformed nature of education since 1986.**

Therefore, against this background, NEP 2020 is a historic step taken under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. This reform requires massive exercise. The process has already begun, and the country is reawakened to recognise its civilisational past and

continuity. What gives every Indian pride is the fact of our civilisational continuity. NEP 2020 aims to ensure this civilisational continuity. This is a milestone in the post-independence Bharat. It believes in connecting Indians with their cultural roots. The shift to this order of thinking considers knowledge of culture, tradition, and science and technology as the essence of education. Bharat has taken up a different journey. It is the journey of impactful difference. Under the leadership of Narendra Modi, Bharat has become a bankable partner of the global north and an inspiring leader of the global south. The international image of Bharat has risen to an incomparable height. This new Bharat believes in its civilisational ethos and relies on its values to develop enduring relationships with the countries in the neighbourhood and globally.

For being once again a knowledge civilisation, the content of the education system ought to be changed. Duty, patriotism, respect for tradition,



retention and expansion of Bharat's knowledge traditions and lacing science with dharma are the aspirations of NEP 2020. Making Bharat self-reliant is its main mantra. The five pillars that the NEP 2020 is based on are Access, Equity, Quality, Affordability, and Accountability. Value and vocation constitute its cardinal features. It addresses three Es - Educate, Encourage and Enlighten. It aims to develop problem-solving competencies and self-reliance among learners. The main focus is the protection of Indian languages, traditions of art, aesthetics, culture, craft, music, literature, etc. Recognising the local artists, musicians, craftsmen, and organic intellectuals and giving them the academic space to disseminate their skills and talents are some of the provisions of NEP 2020. This makes the teaching-learning environment more eclectic, interdisciplinary and enduring.

Its core commitment is fostering rational thinking and an ethical attitude (integrity, empathy, respect, and

responsibility). NEP 2020 adds immensely to the vision of self-reliance and Viksit Bharat. Viksit Bharat is a ground-breaking idea that PM Modi conceived. This vision essentialises a collective preparedness and resolve to make India achieve its best and realise its full potential by 2047 through unprecedented prosperity and development. The focus is given to the youth. The youth of the country is expected to lead this roadmap of progress. Here, education plays a vital role in training the youth in nation-building and understanding their duty to their country and its progress. Comprehensive and sustainable development is its core aspiration. Engaging youths in the developmental process makes the nature of development more enduring. NEP 2020 prepares the youth to participate and contribute through innovative ideas and technologies.

The conception of Amrit Kaal is the commitment to Aatmanirbhar Bharat in the next 25 years. Bharat is a young country, and the youth are an asset.

It will be done in the next 25 years if it has anything exceptional to achieve. Therefore, the youth are engaged constructively, and their energy, intelligence, and creativity are directed toward nation-building and minimising socio-economic gaps. Thus, to raise this awareness, the role of NEP 2020 is crucial. It guides the youth in educating them on their contributions to nation-building and achieving Amrit Kaal by bridging the gap in 25 years. Skill training is an essential part of NEP 2020. Self-reliant youth who work toward innovation, employment generation, etc., are encouraged. Moreover, what seems crucial is the inculcation of patriotism among the youth. It happens through education. Therefore, NEP 2020 contributes immensely to developing a strong sense of patriotism among the youth. If this is done, the Viksit Bharat project will not be far away.

The journey of our education since Independence, which carried much of the colonial model and was penetrated by the left ideologies, was not easy. It specialised in uprooting India from its civilisational ground. This cultural deracination project continued for over a few decades. The modern Indian history developed its antithesis after a long spell of lethargy. NEP 2020 may be conceived as an antithesis that aims to reverse the unreformed nature of education since 1986. It will act as an effective catalyst to decolonise the Indian mind and trigger a crucial shift in perception. □







## Viksit Bharat & Sustainable Development



**Dr. R. Krishna Chaitanya**

Associate Professor,  
Department of Life  
Science, Central  
University of Karnataka

In 1987, the World Commission on Environment and Development (WCED) published a report entitled 'Our common future' wherein the term 'sustainable development' was 'officially' defined for the first time as "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) were adopted in the UN Sustainable Development Summit at New York by all 193 United Nations member states in September 2015 which are to be achieved by the

year 2030. Sustainable living and lifestyles for the first time appear in the Sustainable Development Goals.

United Nations Environment Programme (UNEP) defined sustainable living as "Creating sustainable lifestyles means rethinking our ways of living, how we buy and what we consume but, it is not only that. It also means rethinking how we organize our daily life, altering the way we socialize, exchange, share, educate and build identities. It is about transforming our societies towards more equity and living in balance with our natural environment."

The concept of sustainable development through sustainable living and thinking which the world has recently realized is neither a modern nor novel concept to Bharat. The idea of sustainability has been inherently

engrained in the Indian thought process since age timeless. Harmony and co-existence between humans and nature is deeply rooted in the Indian culture, tradition, ethos and even life styles.

अयं निजः परो वेति  
गणना लघुचेतसाम् ।  
उदारचरितानां तु  
वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

The above verse is from the Maha Upanishad. The English translation of this verse is as follows: This is mine and that is his, say the narrow-minded, the wise believe that the entire world is a family.

The below mantra is from the Taittiriya Upanishad:

ॐ सह नावतु । सह नौ भुनक्तु ।  
सह वीर्यं कर्वावहे ।  
तेजस्वि नावधीतमस्तु ।  
मा विद्विषावहे ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

which is translated as: May we

all be protected, May we all be nourished, May we work together with great energy, May our intellect be sharpened, Let there be no Animosity amongst us. Peace (in me), peace (in nature), peace (in divine forces)

The WCED report title 'our common future' reflects the above mentioned ancient Indian thoughts.

A key concept in Hinduism refers to the four end goals of a human life as 'Purusartha'. The four purusarthas are Dharma (righteousness, moral values); Artha (prosperity, economic values); Kama (pleasure, love, psychological values); and Moksha (liberation, spiritual values). Excess of Artha and Kama can result in over-indulgence, over-exploitation of resources, obsession with material well-being, and concentration of wealth. Dharma is about performing one's duty the right way without thinking about self and the outcome as well. It is important to strike a balance between the four tenets for a peaceful life. The WCED definition of sustainable development echoes the same meaning.

The concept of environment is imbibed in 'Panchabhuta' concept in Hinduism. Whether it is the individual human body or the larger cosmic body, essentially, they are made of five elements- earth, water, fire, air and sky. The environment is not outside us or not alien to us. They are an inseparable part of our existence. In the Atharvaveda, 'mother earth' is described in one hymn of 63 verses. This famous hymn called as Bhumisukta or Prithivisukta

indicates the environmental consciousness of Vedic seers. Ishavasyam is the concept of understanding the omnipresence of divinity which can take infinite forms. Texts, such as the Bhagavad Gita and the Bhagavad Purana, contain many references to the omnipresence of the divinity, including in rivers, forests, animals and panchabhutas.

Early in the morning, we worship Mother Earth with the following sloka

"Samudra vasane devi, Parvata sthana mandale,

Vishnu patnir namastubhyam, Padasparsham kshamasvame"

which is translated as: Goddess who is clothed by the seas and mountains, Consort of Vishnu, Pray forgive me for stamping on you.

Water is the most precious resource for sustainable living. We

**Globally, habitat fragmentation, industrialization, pollution & urbanization etc. are prime reasons for this grave environmental condition and climate change. However, in the past few centuries, mindless imitation of western culture and practices and disconnecting from the ancient roots of wisdom are Indian-specific syndromes. Predominantly, we have been a practice-based civilization when it pertains to environment. Western thought process is mostly evidence-based.**

consider water bodies as holy and also personified many rivers as goddesses. While bathing, we recite a sloka

गङ्गे च यमुने चैव  
गोदावरि सरस्वति ।  
नर्मदे सिन्धु कावेरि  
जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॥

which means: O Holy Rivers Ganga, Yamuna, Godavari and Saraswati,

O Holy Rivers Narmada, Sindhu and Kaveri; Please be present in this water (and make it holy).

The Convention on Biological Diversity (CBD) whose main objective is the conservation of biological diversity and the sustainable use of the components of biological diversity came into effect on 29 December 1993. Biological diversity is defined as the variety of life on earth including plants, animals and microorganisms.

Ancient Indian culture in the form of mythology, spiritual and sacred beliefs & folklore stories imbibed inseparable and intimate bonding between man and biodiversity. For example the Sanskrit shloka, "Ayi Jagadamba Madamba Kadambavanapriya-vaasini Haasarathe," which means that Goddess Durga likes to live in the forest of Kadamba trees.

Tridalam Trigunakaram|  
Trinetrancha Triyaayudham|  
Trijanma Paapa Samharam|  
**Eka Bilvam Shivarpanam||**

This means offering of a bilvapatra (Bael leaves) to god Shiva will wash away the sins committed in the past.

Many medicinal trees and plants including Brahmakamal (Saussurea obvallata), Peepal/ Bodhi (Ficus religiosa), Bargad

(Ficus benghalensis), Bael (Aegle marmelos), Tejbal (Zanthoxylum armatum), Tulsi (Ocimum sanctum), Neem (Azadiracta indica), Khejri (Prosopis cineraria), Rudraksh tree (Elaeocarpus ganitrus) are considered sacred in Hinduism and planted across roads, and in villages and common households.

Indian texts written by scholars revealed their in-depth knowledge of plants and trees and their ecological significance. Panini (4th century BC) described several trees in Ashmadhyayi; Shudraka (100 BC) provided an account of gardens and flowers in Mrichhakatikam; Varahamihira, a learned botanist of 5th century AD, compiled the text Brihat Samhita which described plant pathology. Likewise, Surapala's Vrikshayurveda (tenth-century treatise) includes complete plant-life knowledge compendium of plant physiology, horticulture, pathology, and treatment. Sarangadhara (1300 AD) has described the art of gardening in his texts, Upavana Vinoda and Sarangadhara Paddhati. A recent scientific study revealed all the three carbon dioxide fixing pathways C3, C4 and CAM in Peepal tree which is common only for vegetation grown in arid conditions. Another study reported partial capacitance and inductance activity in all the three types of Rudraksha beads unlike other woody structures.

Sacred groves or forests are patches of land protected by indigenous communities. Each sacred grove has a presiding deity associated with it. Indian sacred groves have pre-vedic origin. Sacred groves have cultural and

spiritual significance for many tribal communities that care and protect them over the centuries. An estimate of 100,000-150,000 sacred groves exists in India which is the highest concentration of sacred groves in the world. The Gharo and Khasi tribes of north east India protect the sacred groves. They refrain from picking a fallen fruit or foliage. Gonds of Central India forbid cutting down trees.

The Indian tradition has respected animal sentience and emphasized the importance of compassion towards animals. The idea of non-violence towards animals (pashu ahimsa) was first referred in Yajur veda. The words "ahimsa paramo dharmah" first appeared in the Upanishads. Many animals were represented as vehicles or friends of the gods, which ensured their protection. For example. Bull is associated with Shiva, Mouse with Ganesh, Lion or Tiger with goddess Durga, Eagle with Vishnu, Elephant with Indra, Swan with Saraswathi, Owl with Lakshmi, Peacock with

Murugan, Dog with Kaala Bhairava etc. Further, we worship and rever cows as Kamadhenu which nourishes us and protect from malnutrition; monkeys are divine to us in the form of Hanuman for their evolutionary significance.

Animal conservation is practiced by many communities as a part of rituals. Many mammalian animals has been conserved by the rituals of Idu-Mishmi tribe of Arunachal Pradesh since time immemorial. According to their rituals, they are restricted to kill wild animals including tiger, hoolock gibbon, dear, wild bear, monkey, and some birds. The Bishnoi community form Rajasthan has been protecting green trees and animals since 500 years. The community believes in their guru Jambhoji's teaching of 'sar saanthe runkh rahe to bhi sasto jaan' meaning even if your head gets chopped off to save a tree from being cut, it is a small sacrifice. There are instances where Bishnoi women breastfed orphaned antelope fawns.





The sustainable life style as mentioned by the UNEP reflects in our daily lives as well as community living:

The 2nd sustainable development goal of zero hunger aims to end extreme hunger and malnutrition by providing safe, nutritious and sufficient food all year round to the poor. In India, thousands of temples and many gurudwaras have been offering 'annadanam' or 'langar seva'. Archaeological studies of inscriptions at Sree Vikramachozeeswarar temple indicated the offering of free food system in the form of annadanam dates back to 1088 AD. The langar system was believed to be popularized by Mata Khivi, the wife of second sikh guru, Guru Angad during early 1500 AD.

According to the Food and Agriculture Organisation (FAO), about one-third of the food produced in the world is wasted. Repurposing of food can help alleviate hunger and poverty. Indian culinary practices are sustainable in many ways. To convert scraps and vegetable peels into chutneys; To use low energy methods such as sun drying, salting and fermenting to transform excess produce as pickles; To make yogurt, butter & ghee with excess milk; To make rotis from leftover lentils etc. are few examples of food repurposing. The kannada text of Lingapurana of Gurulinga Desika from 1594 CE describes over 50 types of Indian pickles. Pickle juices are now a days used in sports to prevent cramps in athletes.

Sustainable environmental friendly initiatives for mitigating climate change and protection of

biodiversity are being advocated all over. We have traditionally practiced sustainable living ways in families and communities: Before the advent of refrigerators, we had earthen pots and cutlery; Before the advent of plastic, we ate in banana leaves as plates and porcelain dishes for storage; Before the advent of cement and steel, we constructed houses with mud, cow dung, grass thatches & bamboo; Before the advent of artificial cooling technologies, we escaped long and dry summers using constructions like latticed screens, badgirs or wind channelers, courtyards with shallow water bodies, jharoka windows, shiny redoxide floors, Madras terrace roofs etc. Before the advent of concrete buildings and apartments, we practiced feeding of animals and birds in 'chabutras', 'aangans' and 'verandahs'. Before the advent of packaged foods, we used fresh & seasonal spices, fruits, vegetables and other foods for consumption. The living root bridges made from fig trees; roof-top rain water harvesting and step well systems; rice-fish cultivation where rice is harvested along with rearing of fish are a few testimonies of our sustainable thinking.

Today, according to the World Air Quality Report 2023 by the Swiss organization IQAir, India ranked third worst out of 134 countries in terms of average annual PM 2.5 concentration. India is the world's third largest greenhouse gas (GHG) emitter. Health professionals are reporting increasing cases of asthma and lung issues among children and the elderly because of the worsening air quality index in the Indian

capital. In the year 2021, a sudden flash flood in the Rishi and Dhauli Ganga rivers in Uttarakhand killed many people. Two hydropower projects were completely destroyed. Avalanches are constantly being reported from Himachal Pradesh. The recent Karnataka water crisis has affected more than 7,000 villages due to dried borewells. Intense cyclonic activity due to increased atmospheric warming in the Indian ocean has resulted in 27 cyclones from Jan, 2019 to Dec, 2023. International Union for the Conservation of Nature declared the extinction of 160 species in the last decade. 24 species of flora and fauna vanished from India in the last few centuries.

Globally, habitat fragmentation, industrialization, pollution & urbanization etc. are prime reasons for this grave environmental condition and climate change. However, in the past few centuries, mindless imitation of western culture and practices and disconnecting from the ancient roots of wisdom are Indian-specific syndromes. Predominantly, we have been a practice-based civilization when it pertains to environment. Western thought process is mostly evidence-based. Do we need to wait for evidences of environmental degradation to protect the environment we live in? We don't need to preach anyone. We just need to practice our Dharma with all honesty and humility. Our dharma is put human 'ego' aside and to take care of the 'eco'. The idea of Vikasit Bharat by 2047 should be about sustainable development. Our very existence as a human race is dependent on it. □

As the world eagerly anticipates India's centennial celebrations in 2047, the Amrit Kaal vision stands as a beacon of hope, guiding the nation towards a future where it assumes its rightful place as a global superpower, shaping the destinies of billions and inspiring nations worldwide to follow in its footsteps. Bharat's awakening is upon us, and the world watches in awe as this ancient civilization writes a new chapter in the annals of global leadership.



## Bharat's Amrit Kaal : The Vision of an Emerging Global Powerhouse



**Darshan Kumar**

Teacher  
Poonch JK (UT)

In a significant era where nations struggle for preeminence on the world stage, Bharat stands poised to engrave its name in the annals of history as a resurgent superpower. The dawn of 'Amrit Kaal,' an ambitious vision unveiled by Prime Minister Narendra Modi, heralds a transformative blueprint that seeks to propel Bharat to the forefront of global leadership by 2047 - the centennial celebration of its independence.

This audacious initiative has captured the imagination of the international community, with influential voices hailing India's ascent as an economic,

technological, and geopolitical force to be reckoned with. As the world eagerly anticipates this Asian behemoth's rise, Bharat is leaving an indelible mark through its unwavering commitment to sustainable development, technological prowess, and social equity.

### **Sustainable Vanguard : Embracing a Greener Future**

At the heart of India's Amrit Kaal vision lies a steadfast commitment to sustainable development, a pursuit that has garnered international acclaim. The country has set ambitious targets to combat climate change, transitioning towards a greener future with a sharp focus on renewable energy sources. According to the International Energy Agency, India is poised to become a

renewable energy juggernaut, with its solar and wind energy capacities projected to surpass coal-fired power by 2030.

India's ambitious target of achieving 450 GW of renewable energy capacity by 2030 - a staggering figure unparalleled in global efforts against climate change - has been hailed as a game-changer. The World Bank's prestigious Ease of Doing Business report has consistently ranked India among the top 10 reforming nations, recognizing its strides in promoting sustainable urban development and creating an enabling environment for businesses to thrive.

### **Digital Dominance : Unleashing the Power of Innovation**

India's meteoric rise as a global technology powerhouse is a cornerstone of its Amrit Kaal

vision. The nation has emerged as a hub for innovation, fostering a thriving startup ecosystem that boasts over 100 unicorns and attracts billions in investments. According to NASSCOM, India's IT industry is projected to reach a staggering \$350 billion by 2025, with the country's digital economy expected to cross the \$1 trillion mark in the same year.

Initiatives like Digital India and the National Education Policy 2020, which emphasize skill development in emerging technologies such as artificial intelligence, block chain, and cyber security, have garnered global attention and praise. India's growing digital economy, boasting over 600 million internet users in 2020, has created a fertile ground for innovation and entrepreneurship, attracting global investors and technology giants.

### **Socio-Economic Transformation : Empowering the Masses**

Underpinning India's Amrit Kaal vision is a steadfast commitment to social justice, inclusivity, and economic empowerment. The country's remarkable strides in alleviating poverty have been lauded by the World Economic Forum, with the percentage of people living in extreme poverty dropping from a staggering 60% in 1990 to just 12.4% in 2019.

Initiatives like the Ayushman Bharat healthcare scheme, which provides affordable healthcare to millions, and the Pradhan Mantri Awas Yojana, an ambitious housing program, have transformed the lives of countless Indians. The Right to Education Act has ensured access to quality

education for all, fostering an inclusive and equitable society - a crucial step in harnessing the nation's vast human potential.

### **A Space Odyssey : Conquering New Frontiers**

India's space program has achieved remarkable milestones, showcasing its technological prowess and cementing its status as a space exploration powerhouse. Successful missions to Mars and the Moon have not only captivated the world but have also paved the way for international collaborations and global recognition of India's capabilities in this arena.

### **Global Acclaim : A Superpower Ascendant**

India's rapid progress towards realizing its Amrit Kaal vision has garnered widespread international recognition and admiration. The country's COVID-19 vaccination drive, hailed as one of the largest and most successful in the world, has been widely praised for its execution and impact. As of September 2021, India had administered over 1 billion doses, safeguarding public health and facilitating economic recovery - a remarkable feat that has captured global attention.

Leading voices from around the world have acknowledged India's ascent, with Christine Lagarde, President of the European Central Bank, predicting, "India's economic might and technological advancements will play a pivotal role in shaping the new world order." UN Secretary-General António Guterres commended India's renewable energy ambitions, stating, "India's commitment to sustainable

development is an inspiration for all nations."

During his visit to the country, President Joe Biden of the United States remarked, "The world is witnessing the birth of a new India - a nation that is confident, capable, and ready to lead."

### **A Vision Realized : India's Destiny Beckons**

As India continues its relentless march towards realizing the Amrit Kaal vision, the international community is taking note. From global financial institutions to renowned think tanks, a resounding chorus of praise and optimism resonates, heralding India's emergence as a preeminent force on the global stage.

With its burgeoning economy, rapidly advancing technology sector, and commitment to sustainable development and social equity, India is poised to redefine the contours of global leadership. The nation's demographic dividend, with a median age of just 28 years, provides a vast pool of human capital, brimming with creativity, innovation, and ambition.

As the world eagerly anticipates India's centennial celebrations in 2047, the Amrit Kaal vision stands as a beacon of hope, guiding the nation towards a future where it assumes its rightful place as a global superpower, shaping the destinies of billions and inspiring nations worldwide to follow in its footsteps. Bharat's awakening is upon us, and the world watches in awe as this ancient civilization writes a new chapter in the annals of global leadership. □





## Amrit Kaal's Hydroponic Harvest : Sustainable Farming for India's Future Flourish



**Dr. Gurdev Chand**

Division of Plant Physiology,  
Faculty of Basic Sciences  
Sher-e-Kashmir University of  
Agricultural Sciences and  
Technology, Jammu

In the pursuit of sustainable and advanced agricultural practices, the article explores the integration of cutting-edge hydroponic technologies to revolutionize traditional farming methods. The word sustainable development means use of all natural resources but in a right manner i.e., without depleting them and can also be used by future generation easily. With the increase in population of the world, the demand for food, water and other resources is increasing day by day. According to the report of Food Agriculture

Organization, (2022) land and water resources and the way they are used play a principal role in food security and these resources are at risk due to demographic pressure, climate change and increased competition. So, to ensure food security and nutrition improvement, agricultural

production will have to rise faster than population growth by about 70% globally which will depend majorly on existing agricultural land.

### **Traditional Farming :**

In contemporary agriculture, traditional farming methods face significant challenges in meeting



the escalating demands of a growing global population while contending with the constraints imposed by dwindling natural resources and environmental sustainability. The need for innovative solutions is evident, and within this context, the article, "Sustainable and advanced agricultural practices: empowering agriculture through hydroponics excellence," aims to address a pressing problem. The problem at hand lies in the inefficiencies and limitations inherent in conventional agricultural practices. Soil-based cultivation, reliant on unpredictable weather patterns and subject to the depletion of arable land, is struggling to keep pace with the increasing demand for food production. According to the 29th report on "Impact of chemical fertilizers and pesticides on agriculture and allied sectors in the country," 42% of India's districts use 85% of chemical fertilisers. The situation is grimmer in major agricultural states like Punjab and Haryana where NPK use ratios are as high

**This article embarks on a journey to unravel the potential of hydroponics as a catalyst for revolutionizing traditional agricultural paradigms. Hydroponics, as an advanced cultivation method, offers a promising avenue for sustainable and efficient crop production. This proposal seeks to delve into the intricate dynamics of hydroponics excellence, examining how its strategic implementation can empower agriculture on multiple fronts.**

as 31.4:8.0:1 and 27.7: 6.1:1 respectively. Hydroponics is much more effective than conventional farming as it recorded a 350% yield increase per unit of land, used 90% less water and 75% less land. Moreover, the environmental impact of conventional farming, including water usage and chemical runoff, raises concerns about long-term sustainability. It is

important to heal our land when we over-utilize it. But the point is which practice will lead to the overall sustainable development and how the future of food production will look like. Why we need to destroy hectares of forests to fulfil the requirement of people? How we will be going to feed the masses in 2030? What if, we will provide minerals or other essential resources to plant artificially without disturbing the nature? The answers to these questions might not be as depressing as we think.

### **Transformative Solution**

Hydroponics, as a soil-less cultivation method, offers a revolutionary approach that optimizes resource usage, enhances crop yields, and minimizes environmental impact. Hydroponics involves cultivating plants in a nutrient-rich water solution, eliminating the need for traditional soil. Instead, plants receive essential nutrients directly, allowing for precise control over their growing conditions. This method provides several advantages, including.

**1. Resource Efficiency :** Hydroponics significantly reduces water usage compared to conventional farming, making it an environmentally sustainable option, especially in water-scarce regions. The controlled environment also minimizes the need for pesticides and fertilizers, contributing to eco-friendly and cost-effective cultivation.

**2. Year-Round Crop Production :** Hydroponics allows for continuous and predictable crop production regardless of external weather conditions. This



adaptability ensures a stable food supply throughout the year, mitigating the impact of seasonal variations on agriculture.

**3. Space Optimization :** By eliminating the requirement for expansive fields, hydroponics enables vertical farming and other space-efficient configurations. This is particularly advantageous in urban areas where available agricultural land is limited.

**4. Enhanced Crop Yields :** The controlled nutrient delivery and environmental conditions in hydroponic systems promote faster and more abundant plant growth. This results in higher crop yields per square foot compared to traditional farming methods.

**5. Reduced Environmental Impact :** Hydroponics minimizes soil erosion, chemical runoff, and other environmental concerns associated with traditional farming. It offers a more sustainable and eco-friendly approach to agriculture.

Green leafy vegetables, fruits like berries, medicinal plants,

flowers and spices can easily grow under hydroponics. Now a days, in Jammu and Kashmir, many farmers are adopting modern techniques for effective, efficient and economic growth in agriculture. Prime Minister Narendra Modi also advised on less use of chemical, fertilizers and pesticides and his government's various initiative lead to the organic farming in India. In order to save our agriculture economy "Zero Budget Farming" was introduced, which focus on farming methods that involve zero credit for agriculture and no use of chemicals and fertilisers. In summary, the proposed solution envisions harnessing the power of hydroponic excellence to empower agriculture.

**Conclusion :**

As the hydroponic initiative unfolds, it holds the promise of not just cultivating crops but cultivating innovation, resilience, and a sustainable future for agriculture. The journey ahead involves continuous learning,

community collaboration, and an unwavering commitment to the principles of excellence and empowerment. In the dynamic landscape of agriculture, the need for transformative solutions has never been more urgent. As we stand at the intersection of population growth, environmental challenges, and the demand for sustainable practices, it becomes paramount to explore innovative approaches that can redefine the very essence of cultivation. This article embarks on a journey to unravel the potential of hydroponics as a catalyst for revolutionizing traditional agricultural paradigms. Hydroponics, as an advanced cultivation method, offers a promising avenue for sustainable and efficient crop production. This proposal seeks to delve into the intricate dynamics of hydroponics excellence, examining how its strategic implementation can empower agriculture on multiple fronts. Beyond its technological intricacies, the research explores the socioeconomic and environmental impacts of integrating hydroponic practices into mainstream agriculture. As we navigate the complexities of feeding a growing global population, this is not merely an exploration of cultivation techniques but a visionary quest to harness innovation in a manner that transcends traditional boundaries. The goal is clear - to empower agriculture through the excellence of hydroponics, fostering a more resilient, resource-efficient, and productive future for farming communities. □







## Holistic Learning : AmritKaal's Blueprint for India's Educational Renaissance



**Ajay Maini**

DRP DIET  
Poonch, J&K

As India strides towards its centenary of independence in 2047, the Amrit Kaal vision emerges as a beacon of transformative change in the nation's educational landscape. Rooted in ancient wisdom and propelled by a modern vision, Amrit Kaal seeks to redefine education, nurturing the holistic development of individuals and preparing them to thrive in a rapidly evolving world.

### **Ancient Wisdom: The Panchakoshas Framework**

In the rich tapestry of ancient Indian philosophy, the concept of

Panchakoshas or five sheaths provides a holistic understanding of human existence. These layers—annamaya kosha (physical), pranamaya kosha (life force energy), manomaya kosha (mind), vijnanamaya kosha (intellect), and anandamaya kosha (inner self)—highlight the interconnectedness of physical, mental, and spiritual dimensions.

Amrit Kaal recognizes the importance of nurturing each kosha for the holistic development of individuals. Practices are designed to develop these layers, acknowledging their interdependence. For instance, physical development is promoted through balanced nutrition, traditional games, and yoga, fostering not only physical health but also mental well-being.

Similarly, cultural immersion through stories, songs, and prayers nurtures language skills and instills values, fostering emotional growth.

### **Modern Vision: The Tenets of Amrit Kaal**

At the core of Amrit Kaal lies a reimagined education system, meticulously crafted to address the multifaceted needs of learners in the 21st century. Let's delve into the key pillars of this visionary approach:

**1. Holistic Development :** Amrit Kaal recognizes that education goes beyond academics, nurturing creativity, critical thinking, emotional intelligence, and vocational skills alongside traditional subjects. By fostering holistic development, schools and colleges become incubators of

well-rounded individuals capable of navigating life's complexities.

**2. Inclusivity and Quality :** Accessible, high-quality education is central to Amrit Kaal, bridging the gap between urban and rural areas, marginalized communities, and economically disadvantaged students. Inclusive policies ensure that every individual has the opportunity to unlock their full potential.

**3. Curriculum Reforms :** The curriculum undergoes a profound transformation, integrating practical skills, vocational training, and interdisciplinary learning. Project-based approaches and real-world applications prepare students for the dynamic demands of the future.

**4. Digital Literacy and Technology Integration :** Embracing the digital age, Amrit Kaal harnesses technology for effective teaching, learning, and assessment. Students are equipped with digital literacy and coding skills, ensuring they are prepared for the jobs of tomorrow.

**5. Teacher Training and Professional Development :** Continuous training and support empower educators to enhance their teaching methodologies and expertise in vocational education and skill development. Investing in teachers ensures that students receive a high-quality education tailored to their needs.

**6. Research and Innovation :** A culture of research and innovation permeates the education system, encouraging students to engage in scientific

inquiry and exploration. Collaboration with industries and research institutions drives progress and discovery.

**7. Flexible Learning Pathways :** Amrit Kaal introduces flexible learning pathways, allowing students to pursue personalized educational trajectories and lifelong learning. Multiple entry and exit points facilitate seamless transitions and empower individuals to pursue their passions.

**8. Cultural Heritage and Local Languages :** The preservation of cultural heritage and local languages strengthens identity and fosters a sense of belonging. Indigenous knowledge systems enrich the educational

experience, promoting cultural diversity and inclusivity.

**9. Assessment Reforms :** Assessment methods evolve to move beyond rote memorization, embracing continuous evaluation and vocational skill assessments. Graded accreditation ensures that quality standards are maintained, reflecting the true capabilities of students.

**10. Global Citizenship and Social Responsibility :** Amrit Kaal nurtures responsible global citizens, instilling values of environmental sustainability, social justice, and civic engagement. Volunteering and community service become integral components of education, shaping compassionate and empathetic individuals ready to contribute to society.

**Integrating Ancient Wisdom with Modern Vision**

The Panchakoshas framework provides a timeless understanding of human development, complementing the modern vision of Amrit Kaal. By interweaving ancient wisdom with contemporary approaches, India's educational future is shaped by a holistic, inclusive, and forward-looking paradigm.

In conclusion, Amrit Kaal heralds a new era in Indian education—one that honors tradition while embracing innovation, one that fosters individual growth while nurturing collective well-being. As India marches towards its tryst with destiny in 2047, the vision of Amrit Kaal illuminates the path towards a brighter, more equitable future for all. □

**In conclusion, Amrit Kaal heralds a new era in Indian education—one that honors tradition while embracing innovation, one that fosters individual growth while nurturing collective well-being. As India marches towards its tryst with destiny in 2047, the vision of Amrit Kaal illuminates the path towards a brighter, more equitable future for all.**

**शैक्षिक मंथन**

(मासिक)

प्रकाशन तिथि : 1 मई 2024

प्रेषण दिनांक : 7 मई 2024, सी.एस.ओ. गाँधीनगर, जयपुर

पंजीयन क्र. : आर.एन.आई. राजबिल/2008/26080

डाक पंजीयन क्र. : आई.आर./जयपुर सिटी/434/2024-26



**सुंदरता तब ही अच्छी लगती है जब मन के भाव भी शुद्ध एवं पवित्र हों। आपके मन के भाव ही आपके चेहरे पर झलकते हैं।**

**- संत रामानुजाचार्य**

कृपया अचितरित होने पर लौटावें :

प्रकाशकीय कार्यालय

**शैक्षिक मंथन**

82, पटेल कॉलोनी,

सरदार पटेल मार्ग, जयपुर - 302 001

प्रकाशक, मुद्रक - महेन्द्र कपूर, स्वत्वाधिकारी  
शैक्षिक मंथन संस्थान द्वारा प्रीमियर प्रिंटिंग प्रेस,  
प्लॉट नं. 12, रामनगर, सोडाला, जयपुर से मुद्रित।  
सम्पादक - डॉ. शिवशरण कौशिक